Resilient India - Disaster Free India

सत्यमेव जयते

टाइडिंग्स

एनआईडीएम पत्रिका–03/2026
अप्रैल-जून, 2026

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
(गृह मंत्रालय, भारत सरकार)

वेबसाइट: https://nidm.gov.in

/nidmmhaindia /nidmmhaindia /nidmmhaindia /nidmindia /nidmmhaindia

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान संबंधी जानकारी

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) की स्थापना संसद के एक अधिनियम के तहत भारत और इस क्षेत्र में क्षमता विकास के लिए एक प्रमुख संस्थान के रूप में भूमिका निभाने के दृष्टिकोण के साथ किया गया था। इस दिशा में जो प्रयास वर्ष 1995 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र (एनसीडीएम) की स्थापना के साथ शुरू हुई थी, उन्हें प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) के रूप में फिर से नामित किए जाने के बाद और अधिक गति प्राप्त हुई।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, अनुसंधान, प्रलेखन एवं पॉलिसी एडवोकेसी से संबंधित नोडल जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

एनआईडीएम ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण को राष्ट्रीय एजेंडा के केंद्र में लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संस्थान का मानना है कि सभी हितधारकों की सहभागिता से ''रोकथाम की संस्कृति'' को बढ़ावा देकर ही आपदा जोखिम न्यूनीकरण संभव है। एनआईडीएम केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों, देश-विदेश की शैक्षणिक, अनुसंधान एवं तकनीकी संस्थाओं तथा अन्य द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ रणनीतिक साझेदारियों के माध्यम से कार्य करता है।

एनआईडीएम को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के अलग-अलग पहलुओं पर कार्य करने वाले बहुआयामी विषयों के पेशेवरों की टीम पर गर्व है। प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास को सुगम बनाने के अपने प्रयासों के अंतर्गत, संस्थान में अत्याधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जिनमें क्लास रूम, सेमिनार हॉल, वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएँ आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, संस्थान में आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषय पर एक सुव्यवस्थित और समृद्ध पुस्तकालय भी है।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में एनआईडीएम विभिन्न राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय एजेंसियों को क्षमता निर्माण में भी सहयोग प्रदान करता है। संस्थान का लक्ष्य आपदा रोकथाम एवं तैयारी के लिए सभी स्तरों पर क्षमता का विकास कर एक आपदा-रोधी भारत का निर्माण करना है।

NIDM पत्रिका 03/2026

अप्रैल–जून, 2026

संपादकीय मंडल

प्रधान संपादक
श्री मधुप व्यास, भा.प्र.से.
कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम

संपादक
डॉ. अजिंदर वालिया
एसोसिएट प्रोफेसर

संपादकीय सहायता
(डिजाइन एवं प्रस्तुति)
सुश्री नाज़िया खान
वरिष्ठ परामर्शदाता, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी

सह-संपादक
डॉ. रविन्द्र सिंह
वरिष्ठ परामर्शदाता

डॉ. कुंदन देवल
परामर्शदाता

अनुवादक
संजय कुमार
परामर्शदाता, राजभाषा

विषय सूची

1.	संदेश	2
2.	एसीआरसी 2026	3
3.	आमने-सामने प्रशिक्षण कार्यक्रम	5
4.	सम्मेलन/कार्यशाला/सेमिनार/परामर्श बैठक	18
5.	अन्य संस्थागत क्रियाकलाप	28
6.	विषयगत दृष्टिकोण	31
7.	एनआईडीएम प्रकाशन	42
8.	एनआईडीएम पोर्टल्स	43

आंतरिक विषय-वस्तु

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

आपदा प्रबंधन राहत आयुक्तों का वार्षिक सम्मेलन (एसीआरसी)- 2026 — 3

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों हेतु चौथा भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम, 01-12 जून 2026, दिल्ली — 9

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय और पत्तन प्राधिकरणों के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 15-18 जून 2026, दिल्ली — 11

आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रत्यास्थता शिक्षा पर यूएनडीआरआर-गेटी (UNDRR-GETI) कार्यशाला में एनआईडीएम की सहभागिता — 28

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम)
कार्यकारी निदेशक का संदेश

प्रिय पाठकों,

अत्यन्त प्रसन्नता के साथ मैं टाइडिंग्स का यह अंक (अप्रैल-जून 2026) आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस अवसर पर अपने सहयोगी संस्थानों, भागीदारों एवं हितधारकों से पुनः जुड़कर संवाद स्थापित करना भी मेरे लिए हर्ष का विषय है।

गत तिमाही के दौरान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने क्षमता निर्माण, ज्ञान प्रसार, अनुसंधान, नवाचार तथा संस्थागत सहयोग के क्षेत्र में अपनी गतिविधियों का विस्तार किया। पारंपरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ-साथ iGOT कर्मयोगी मंच पर उपलब्ध संस्थान के ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को भी व्यापक सहभागिता प्राप्त हुई, जिसमें अब तक 2,74,990+ नामांकन तथा 1,84,860+ पाठ्यक्रम पूर्णताएँ दर्ज की गई हैं। संस्थान द्वारा व्यापक आपदा प्रबंधन पाठ्यक्रम, भारतीय प्रशासनिक सेवा- 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों हेतु अभिमुखीकरण कार्यक्रम, प्रथम मास्टर ट्रेनर विकास कार्यक्रम तथा विभिन्न विषयगत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया गया, जिनका उद्देश्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं जोखिम-सूचित विकास के लिए संस्थागत क्षमताओं को सुदृढ़ करना रहा।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग को और सशक्त बनाते हुए एनआईडीएम ने एशिया एवं अफ्रीका के 11 देशों के प्रतिभागियों की सहभागिता के साथ चौथे आईटीईसी अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया। मुझे आपदा प्रत्यास्थता के क्षेत्र में वैश्विक ज्ञान-विनिमय तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कोरिया गणराज्य के इंचियोन में आयोजित यूएनडीआरआर-गेटी कार्यशाला में एनआईडीएम का प्रतिनिधित्व करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। क्षमता निर्माण, अनुसंधान, डिजिटल अधिगम, नवाचार तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्रों में संस्थान के प्रयास निरंतर विस्तार पा रहे हैं।

एनआईडीएम को वर्ष 2026 के राहत आयुक्तों/आपदा प्रबंधन सचिवों, राज्य आपदा मोचन बलों तथा अग्निशमन, नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड प्रमुखों (राज्य/केंद्रशासित प्रदेश) के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी का अवसर प्राप्त हुआ। यह सम्मेलन आपदा तैयारी की समीक्षा, विभिन्न हितधारकों के मध्य समन्वय को सुदृढ़ करने तथा उभरते आपदा जोखिमों पर विचार-विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मंच सिद्ध हुआ। सम्मेलन के दौरान माननीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया द्वारा सेल ब्रॉडकास्टिंग प्रणाली (सीबीएस) का शुभारंभ किया गया, जो आपदा पूर्व चेतावनी एवं आपातकालीन संचार तंत्र को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

मुझे यह साझा करते हुए भी प्रसन्नता है कि क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) के राष्ट्रीय मानकों के अंतर्गत एनआईडीएम को 4-स्टार रेटिंग (अति उत्कृष्ट) प्राप्त हुई है। यह मान्यता प्रशिक्षण, अनुसंधान, नीतिगत सहयोग, संस्थागत सुशासन एवं क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में संस्थान की उत्कृष्टता और प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से आयोजित 'दक्षिण-पश्चिम मानसून 2026 पर हितधारक बैठक' ने भी विभिन्न विशेषज्ञों एवं संस्थानों को एक मंच पर लाकर पूर्वानुमान आधारित कार्यवाही, सूचित योजना निर्माण तथा जोखिम-संवेदनशील निर्णय प्रक्रिया को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मैं हमारे सभी सहयोगी संस्थानों, विशेषज्ञों, संकाय सदस्यों एवं हितधारकों के निरंतर सहयोग और समर्थन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे आशा है कि हम सभी मिलकर तैयारी, सहभागिता और प्रत्यास्थता की संस्कृति को और मजबूत करेंगे तथा एक सुरक्षित, सशक्त और आपदा-प्रत्यास्थ भारत के निर्माण में अपना योगदान देते रहेंगे।

मधुप व्यास, भा.प्र.से.

आपदा प्रबंधन राहत आयुक्तों/सचिवों, राज्य आपदा मोचन बल, और अग्निशमन सेवाओं, नागरिक सुरक्षा एवं होम गार्ड (राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों) के प्रमुखों का वार्षिक सम्मेलन - 2026, 02 मई 2026, एनआईडीएम, दिल्ली

ACRC 2026 के उद्घाटन सत्र के दौरान माननीय केंद्रीय संचार एवं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री, श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान को 'राहत आयुक्तों/आपदा प्रबंधन सचिवों, राज्य आपदा मोचन बल, और अग्नि शमन सेवाओं, नागरिक सुरक्षा व होम गार्ड (राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों) के प्रमुखों के वार्षिक सम्मेलन - 2026' को आयोजित करने का सौभाग्य मिला। गृह मंत्रालय की देखरेख में आयोजित यह सम्मेलन मॉनसून सीज़न से पहले आपदा प्रबंधन की तैयारी की समीक्षा करने, संस्थागत तालमेल को मज़बूत करने और तकनीक-आधारित आपदा प्रबंधन शासन को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रमुख राष्ट्रीय मंच साबित हुआ। इस सम्मेलन में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों, रिस्पॉन्स फ़ोर्स, वैज्ञानिक संस्थानों और तकनीकी एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 350 से ज़्यादा प्रतिभागी शामिल हुए।

इस सम्मेलन का उद्घाटन माननीय केंद्रीय संचार मंत्री और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने किया। इस मौके पर केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन, एनडीएमए के सदस्य एवं विभागाध्यक्ष डॉ. कृष्ण एस. वत्स, दूरसंचार विभाग के सचिव श्री अमित अग्रवाल, एनडीआरएफ के महानिदेशक श्री पीयूष आनंद, गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव (आपदा प्रबंधन) श्री अनुज शर्मा और एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक श्री मधुप व्यास (भा.प्र.से.) भी मौजूद थे। उद्घाटन सत्र में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि जोखिम भरे और जटिल होते माहौल में आपदा से निपटने की क्षमता (डिज़ास्टर रेज़िलिएंस) को मज़बूत करने के लिए "पूरी सरकार" और "पूरे समाज" के नज़रिए को अपनाना ज़रूरी है।

इस सम्मेलन की एक मुख्य बात 'सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार' का दिया जाना था, जिसके ज़रिए आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में संस्थानों और व्यक्तियों के बेहतरीन योगदान को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में 'सेल ब्रॉडकास्टिंग सॉल्यूशन' (CBS) को भी लॉन्च किया गया। यह भारत के 'प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली' को मज़बूत करने की दिशा में एक अहम कदम है, जो जियो-टारगेटेड और रियल-टाइम इमरजेंसी अलर्ट देता है। CAP-आधारित 'सचेत' (SACHET) प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े इस सिस्टम से देश भर में 'लास्ट-माइल कनेक्टिविटी' और आपदा के समय होने वाले कम्युनिकेशन को काफ़ी बेहतर बनाने की उम्मीद है।

माननीय मंत्री महोदय ने इस अवसर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तैयार ''पशु-समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी दिशा-निर्देश'' तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के प्रकाशन ''आपदा एवं संवेदनशीलता की अवधारणा : शिक्षाविदों के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर हैंडबुक'' का भी विमोचन किया। इन ज्ञानवर्धक प्रकाशनों से समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण को सुदृढ़ बनाने, शैक्षणिक सहभागिता को बढ़ावा देने तथा साक्ष्य-आधारित नीतियों एवं व्यवहारिक कार्यप्रणालियों को समर्थन प्रदान करने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी।

तकनीकी सत्रों में एनडीएमए, एनडीआरएफ, एनआईडीएम, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र-इसरो (एनआरएससी-इसरो), राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों तथा विभिन्न आपदा प्रतिक्रिया एजेंसियों द्वारा मानसून पूर्व तैयारी, पूर्व चेतावनी प्रणालियों, भूस्खलन पूर्वानुमान, बाढ़ प्रबंधन, सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) अनुप्रयोगों, संस्थागत सुदृढ़ीकरण तथा आपदा प्रतिक्रिया तत्परता जैसे विषयों पर प्रस्तुतियाँ दी गईं। विचार-विमर्श के दौरान आपदा प्रतिरोधक क्षमता को राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सुदृढ़ बनाने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग, डेटा-आधारित योजना निर्माण, समन्वय तंत्रों को और अधिक प्रभावी बनाने तथा समुदाय-केंद्रित दृष्टिकोणों को अपनाने पर विशेष बल दिया गया।

माननीय केंद्रीय संचार एवं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया एवं केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविन्द मोहन को स्मृति-चिह्न भेंट

सम्मेलन का समापन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य एवं विभागाध्यक्ष डॉ. कृष्ण एस. वत्स की अध्यक्षता में आयोजित समापन सत्र के साथ हुआ। इस अवसर पर राज्य एवं स्थानीय स्तर पर आपदा प्रतिरोधक क्षमता को सुदृढ़ करने हेतु सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श को ठोस एवं क्रियान्वित किए जा सकने वाले कार्यों में परिवर्तित करने के आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया। सम्मेलन के दौरान हुई चर्चाओं ने पूर्व चेतावनी संदेशों के प्रभावी प्रसार, प्रौद्योगिकी-सक्षम आपदा प्रबंधन शासन, संस्थागत क्षमताओं के सुदृढ़ीकरण तथा विभिन्न हितधारकों के मध्य बेहतर समन्वय की आवश्यकता को पुन: रेखांकित किया। सम्मेलन ने आगामी मानसून सत्र से पूर्व तैयारी, आपदा प्रतिक्रिया क्षमताओं के संवर्धन तथा जोखिम-आधारित निर्णय-निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए एक स्पष्ट कार्ययोजना प्रदान की।

आमने-सामने प्रशिक्षण कार्यक्रम

एनआईडीएम दिल्ली परिसर

ग्राम पंचायत विकास योजना में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के एकीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 20-22 अप्रैल 2026, दिल्ली

मुख्य बातें/अनुशंसाएं

क)	ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDP) में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) के समावेशन की समझ को सुदृढ़ करना, जिससे कि जोखिम-सूचित स्थानीय विकास, संसाधनों का प्रभावी आवंटन तथा आपदा-प्रतिरोधी अवसंरचना नियोजन सुनिश्चित किया जा सके।
ख)	ग्राम स्तरीय आपदा प्रबंधन योजना के संबंध में ज्ञान को सुदृढ़ करना, जिसमें खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता एवं क्षमता (HRVC) आकलन, सहभागी नियोजन प्रक्रियाएँ तथा समुदाय-आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण शामिल हैं।
ग)	आपदा प्रबंधन से संबंधित संस्थागत ढाँचे, विधिक प्रावधानों एवं वित्तीय तंत्रों की बेहतर समझ विकसित करना, जिसमें आपदा जोखिम शासन में राष्ट्रीय, राज्य, जिला एवं स्थानीय संस्थाओं की भूमिकाएँ सम्मिलित हैं।

घ)	स्थानीय स्तर पर आपदा प्रतिरोधक क्षमता को सुदृढ़ करने तथा आपदा संबंधी संवेदनशीलताओं को कम करने के लिए सामुदायिक सहभागिता, सामाजिक एवं व्यवहारगत परिवर्तन संबंधी दृष्टिकोणों तथा सहभागी निर्णय-निर्माण के महत्व को पुन: स्थापित करना।
ङ)	जमीनी स्तर पर प्रभावी आपदा तैयारी एवं प्रतिक्रिया के लिए जोखिम आकलन उपकरणों, भू-स्थानिक एवं सहभागी तकनीकों, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों तथा जलवायु अनुकूलन उपायों के अनुप्रयोग में क्षमताओं का संवर्धन करना।
च)	आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपायों को विकास योजनाओं, स्थानीय शासन प्रक्रियाओं तथा सतत् सामुदायिक प्रतिरोधकता पहलों के साथ एकीकृत कर आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के मध्य अभिसरण को प्रोत्साहित करना।

मानसून-पूर्व तैयारी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 06-08 मई 2026, महाराष्ट्र

मुख्य बातें/अनुशंसाएं

क)	समुदाय स्तर पर तुरंत तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए, समय पर चेतावनी की जानकारी फैलाने और उसके प्रभावी इस्तेमाल के महत्व पर ज़ोर दिया गया।
ख)	मानसून के मौसम में बांध प्रबंधन, बाढ़ की तैयारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल के तरीकों की समझ को बेहतर बनाया गया।
ग)	संसाधन मैपिंग, आपातकालीन उपकरणों की पहले से तैनाती और बाढ़-संभावित क्षेत्रों के लिए तैयारी की योजना बनाने में बेहतर क्षमता विकसित हुई।
घ)	प्रतिभागियों को प्रभावी आपदा प्रतिक्रिया के लिए घटना प्रतिक्रिया प्रणाली, स्थिति प्रतिवेदन (Situation Reporting-SITREP) तथा आपातकालीन परिचालन केंद्र की कार्यप्रणाली, संचालन एवं उपयोगिता के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई, जिससे उनकी आपदा प्रबंधन संबंधी दक्षताओं में वृद्धि हुई।
ङ)	संवेदनशील आबादी, निकासी मार्गों तथा महत्वपूर्ण अवसंरचना को समाहित करते हुए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप नियमित रूप से अद्यतन किए जाने वाले आपदा प्रबंधन योजनाओं की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया।

कार्यक्रम निर्माताओं के लिए आपदा-पूर्व प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 11-13 मई 2026, दिल्ली

मुख्य बातें/अनुशंसाएं

क)	प्रतिभागियों में प्रभावी आपदा तैयारी योजना निर्माण हेतु आपदा जोखिम की अवधारणाओं, विभिन्न आपदाओं के जोखिम-प्रोफाइल, संवेदनशीलता आकलन तथा आपदा प्रबंधन चक्र के संबंध में समझ को और सुदृढ़ किया गया।
ख)	जोखिम के प्रति सतर्कता पूर्वक निर्णय लेने एवं प्रभावी संचार के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण की रूपरेखाओं, संस्थागत तंत्रों तथा बहु-आपदा पूर्व चेतावनी प्रणालियों के संबंध में ज्ञान एवं समझ को सुदृढ़ किया गया।
ग)	आपदा-पूर्व संचार रणनीतियों के विकास में प्रतिभागियों की क्षमताओं को उन्नत किया गया, जिसमें पूर्व चेतावनी संदेशों का प्रसार, सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग तथा भ्रामक एवं गलत सूचनाओं के प्रबंधन से संबंधित पहलू शामिल थे।
घ)	प्रतिभागियों की समुदाय-आधारित एवं समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण दृष्टिकोणों के संबंध में दक्षताओं को बढ़ाया गया, जिसमें विशेष रूप से संवेदनशील वर्गों की आवश्यकताओं तथा आपदा प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने में मीडिया की भूमिका पर बल दिया गया।
ङ)	व्यावहारिक अभ्यासों एवं सिमुलेशन-आधारित शिक्षण गतिविधियों के माध्यम से प्रतिभागियों के आपदा संबंधी आंकड़ों के उपयोग, जोखिम संचार तथा आपातकालीन प्रसारण से संबंधित व्यावहारिक कौशलों को और अधिक सशक्त एवं परिष्कृत किया गया।

आपदा जोखिम प्रबंधन पर 16वां समग्र पाठ्यक्रम, 11-22 मई 2026, दिल्ली

मुख्य बातें/अनुशंसाएं

क)	प्रभावी आपदा शासन के लिए आपदा प्रबंधन चक्र, आपदा जोखिम न्यूनीकरण की रूपरेखाओं तथा जोखिम के प्रति सतर्क दृष्टिकोणों के संबंध में समझ को सुदृढ़ किया गया।
ख)	बहु-आपदा जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन हेतु खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता एवं क्षमता (HRVC) आकलन, आपदा नियोजन तथा तैयारी संबंधी गतिविधियों में प्रतिभागियों की क्षमताओं का संवर्धन किया गया।
ग)	प्रतिभागियों को प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, घटना प्रतिक्रिया प्रणाली तथा प्रभावी आपदा तैयारी एवं प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक संस्थागत समन्वय तंत्रों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान कर उनके ज्ञान को सुदृढ़ किया गया।

घ)	उभरते हुए आपदा जोखिमों, बहु-आपदा प्रबंधन दृष्टिकोणों तथा विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यास्थता निर्माण की रणनीतियों के संबंध में समझ को सुदृढ़ किया गया।
ङ)	क्षेत्र के भ्रमण तथा आपदा प्रबंधन, आपातकालीन प्रतिक्रिया, स्वास्थ्य सेवाओं एवं मौसम पूर्वानुमान से संबंधित प्रमुख संस्थानों के साथ संवाद के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव एवं कार्यगत समझ को और बेहतर बनाया।
च)	आपदा जोखिम प्रबंधन एवं सतत् विकास के लिए समुदाय-आधारित, समावेशी तथा आपदा-प्रतिरोधी दृष्टिकोणों के महत्व को और अधिक सुदृढ़ किया गया।

भारतीय खेल प्राधिकरण के अधिकारियों के लिए आपदा प्रबंधन पर संसाधन व्यक्ति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम, 18-22 मई 2026, दिल्ली

मुख्य बातें/अनुशंसाएं

क)	खेल परिसरों से संबंधित आपदा जोखिमों तथा व्यापक जोखिम आकलन एवं आपदा के पूर्व तैयारी आधारित योजना निर्माण की आवश्यकता के संबंध में समझ को सुदृढ़ किया गया।
ख)	खेल सुविधाओं में आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों, राष्ट्रीय भवन संहिता की आवश्यकताओं तथा संस्थागत उत्तरदायित्वों के संबंध में ज्ञान और समझ को सुदृढ़ किया गया।
ग)	जोखिम, संकट, संवेदनशीलता एवं क्षमता आकलन (Hazard, Risk, Vulnerability and Capacity Assessment-HRVCA) के संचालन तथा खेल परिसर-विशिष्ट आपदा प्रबंधन योजनाओं के निर्माण संबंधी क्षमताओं को सुदृढ़ किया गया।

घ)	आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने हेतु घटना प्रतिक्रिया प्रणाली, आपातकालीन संचार प्रोटोकॉल तथा समन्वित प्रतिक्रिया तंत्रों के महत्व पर ज़ोर दिया गया।
ङ)	अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुपालन, भीड़ प्रबंधन तथा समावेशी आपदा तैयारी उपायों को बढ़ावा दिया गया, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए सुगम्यता संबंधी प्रावधानों पर विशेष बल दिया गया।
च)	संस्थागत तैयारी को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए नियमित मॉक ड्रिलों के आयोजन, आपदा प्रबंधन योजनाओं के परीक्षण तथा समय-समय पर उनकी समीक्षा की आवश्यकता को प्रमुखता से रेखांकित किया गया।

एनडीआरएफ अधिकारियों की देखभाल करने वालों के लिए मनोसामाजिक सहायता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 02-04 जून 2026, महाराष्ट्र

मुख्य बातें/अनुशंसाएं

क)	आपदा की तैयारी, उससे निपटने और उबरने के दौरान मनो-सामाजिक देखभाल की अवधारणा, सिद्धांतों और महत्व को समझना; इसमें आपदा के अलग-अलग चरणों में होने वाली मनो-सामाजिक प्रतिक्रियाएं और लोगों में मुश्किलों से उबरने की क्षमता बढ़ाने में समुदाय की भागीदारी की भूमिका शामिल है।
ख)	आपदा-प्रभावित समुदायों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु सात प्रमुख मनोसामाजिक देखभाल तकनीकों—भावनात्मक अभिव्यक्ति, सहानुभूति, सक्रिय श्रवण (जिसमें SOLER मॉडल सम्मिलित है), रुचियों का बाह्यीकरण, सामाजिक सहयोग, मनोरंजन एवं विश्राम गतिविधियाँ तथा आध्यात्मिकता के संबंध में ज्ञान एवं समझ सुदृढ़ हुई।
ग)	बाल-केंद्रित मनोसामाजिक देखभाल के अंतर्गत आयु आधारित हस्तक्षेपों, जैसे खेल, कला, कहानी-कथन, चित्रांकन, स्केचिंग, मिट्टी से मॉडल निर्माण तथा अन्य रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में भावनात्मक अभिव्यक्ति, अनुकूलन क्षमता एवं प्रत्यास्थता को बढ़ावा देने संबंधी समझ विकसित हुई।
घ)	महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों, दिव्यांगजनों, प्रथम प्रतिक्रिया कर्मियों तथा अन्य संवेदनशील समूहों की मनोसामाजिक आवश्यकताओं एवं लैंगिक-संवेदनशील सहायता उपायों की समझ सुदृढ़ हुई। साथ ही, आपदा प्रतिक्रिया के दौरान लैंगिक आधारित हिंसा, मानव तस्करी, यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार से सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा गरिमा एवं समावेशन बनाए रखने के उपायों पर विशेष बल दिया गया।
ङ)	आपदा से प्रभावित व्यक्तियों एवं आपदा प्रतिक्रिया कर्मियों में सामान्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं तथा मनोसामाजिक चुनौतियों, जैसे- तीव्र तनाव, कार्यजनित थकावट, करुणा-जनित थकान, चिंता, अवसाद, शोक तथा आघात के बाद तनाव, विकार की पहचान, उनके लिए उपयुक्त मनोसामाजिक सहायता तथा आवश्यकतानुसार रेफरल तंत्र की जानकारी प्राप्त हुई।
च)	स्व-देखभाल एवं देखभालकर्ताओं के कल्याण से संबंधित उपायों—जैसे माइंडफुलनेस , ग्राउंडिंग अभ्यास, तनाव प्रबंधन तकनीकें, सहकर्मी सहयोग, आपदा प्रतिक्रिया कर्मियों की देखभाल तथा ट्री ऑफ सस्टेनेंस मॉडल के माध्यम से आपदा प्रतिक्रिया कर्मियों की प्रत्यास्थता को सुदृढ़ करने तथा कार्यजनित थकावट की रोकथाम संबंधी ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि हुई।

पर्वतीय क्षेत्रों एवं जलवायु परिवर्तन अनुकूलन क्षमता पर विशेष ध्यान के साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 01-05 जून 2026, दिल्ली

मुख्य बातें/अनुशंसाएं

क)	हिमालयी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरों, जैसे भूस्खलन, बाढ़, हिमनदीय झील के फटने से उत्पन्न बाढ़ (GLOFs), वनाग्नि तथा भूकंप आदि के संबंध में समझ में वृद्धि हुई, जिससे
	जलवायु-अनुकूल एवं आपदा-प्रतिरोधी विकास योजना की आवश्यकता पर बल दिया गया।
ख)	आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं जलवायु परिवर्तन अनुकूलन

	क्षमता को उच्च शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार तथा क्षमता विकास पहलों में समाहित करने संबंधी ज्ञान को सुदृढ़ किया गया।
ग)	बहु-आपदा जोखिम आकलन दृष्टिकोणों तथा जोखिम मानचित्रण, साक्ष्य-आधारित योजना निर्माण एवं सूचना के आधार पर निर्णय लेने के लिए भू-स्थानिक (Geospatial) प्रौद्योगिकियों के उपयोग संबंधी समझ में सुधार हुआ।
घ)	प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, वास्तविक समय निगरानी, पूर्वानुमान उपकरणों तथा आपातकालीन संचार नेटवर्कों के महत्व को पुनः रेखांकित किया गया, जिससे आपदा पूर्व तैयारी को सुदृढ़ करने एवं आपदा जनित क्षति को कम करने में सहायता मिलती है।
ङ)	समुदाय-आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोणों को प्रोत्साहित किया गया, जिसमें स्थानीय क्षमता निर्माण, सहभागितापूर्ण जोखिम आकलन तथा आपदा तैयारी एवं प्रतिरोधक क्षमता निर्माण के प्रयासों में संवेदनशील समूहों की सहभागिता पर विशेष बल दिया गया।
च)	दीर्घकालिक प्रतिरोधक क्षमता एवं सतत् विकास को बढ़ावा देने के लिए सुदृढ़ संस्थागत समन्वय, आपदा जोखिम वित्तपोषण तंत्र तथा निरंतर ज्ञान-साझाकरण मंचों की आवश्यकता को रेखांकित किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों हेतु चौथा भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम, 01-12 जून 2026, दिल्ली

मुख्य बातें/अनुशंसाएं

क)	सहभागी देशों में आपदा जोखिम प्रबंधन प्रणालियों, नीतियों तथा संस्थागत तंत्रों के संबंध में समझ को सुदृढ़ किया गया, जिससे पारस्परिक सीख एवं ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा मिला।
ख)	आपदा जोखिम न्यूनीकरण, आपदा पूर्व तैयारी तथा आपदा प्रतिक्रिया के क्षेत्र में भारत के प्रयासों, श्रेष्ठ प्रथाओं एवं नवाचारों के प्रति जागरूकता में वृद्धि हुई, जिन्हें साझेदार देशों द्वारा आवश्यकतानुसार अपनाया जा सकता है।
ग)	विभिन्न प्रकार के खतरों एवं जोखिम परिदृश्यों के प्रबंधन से संबंधित अनुभवों, चुनौतियों तथा उत्कृष्ट कार्य-पद्धतियों के आदान-प्रदान के माध्यम से देशों के बीच सीखने की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिला।
घ)	भारत की ज्ञान परंपराओं, सांस्कृतिक विरासत तथा प्रत्यास्थता निर्माण और सतत् विकास संबंधी दृष्टिकोणों के प्रति समझ एवं सराहना को और अधिक सुदृढ़ किया गया।
ङ)	प्रतिभागियों, विशेषज्ञों तथा संस्थाओं के मध्य व्यावसायिक नेटवर्क एवं संस्थागत संबंधों को सुदृढ़ किया गया, जिससे भविष्य में आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं क्षमता विकास के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा मिल सके।

स्कूल सुरक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 08-12 जून 2026, दिल्ली

मुख्य बातें/अनुशंसाएं

क)	विद्यालय सुरक्षा को एक पृथक गतिविधि के रूप में न लेकर विद्यालय के वार्षिक विकास एवं प्रबंधन प्रक्रियाओं में समेकित किया जाना चाहिए।
ख)	खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता एवं क्षमता आकलन (HRVCA) साक्ष्य-आधारित विद्यालय सुरक्षा योजना निर्माण का आधार प्रदान करता है।
ग)	स्कूल परिसर में संरचनात्मक, गैर-संरचनात्मक, पर्यावरणीय और कार्यात्मक जोखिमों की पहचान करने की आवश्यकता है।
घ)	गैर-संरचनात्मक जोखिमों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे कि असुरक्षित फर्नीचर, बिजली से जुड़े खतरे, निकासी के अवरुद्ध रास्ते, प्रयोगशाला में सुरक्षा संबंधी चिंताएं और अपर्याप्त संकेत-चिह्नों पर ध्यान देने की जरूरत है।
ङ)	विद्यालय सुरक्षा समितियाँ, घटना प्रतिक्रिया दल तथा स्पष्ट रूप से परिभाषित भूमिकाएँ एवं उत्तरदायित्व प्रभावी तैयारी एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।
च)	संसाधन मानचित्रण, मौसमी कैलेंडर, ट्रांसेक्ट वॉक तथा हितधारक विश्लेषण जैसे सहभागितापूर्ण उपकरण विद्यालय सुरक्षा पहलों में स्थानीय स्वामित्व एवं सहभागिता को सुदृढ़ कर सकते हैं।
छ)	जिला प्रशासन, आपातकालीन सेवाओं, स्थानीय प्रशासन तथा सामुदायिक हितधारकों के साथ नियमित समन्वय को संस्थागत रूप दिया जाना चाहिए।
ज)	शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा सहायक कर्मचारियों को बुनियादी आपातकालीन प्रतिक्रिया, निकासी प्रक्रियाओं तथा प्राथमिक उपचार का नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

मानसून पूर्व तैयारी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 11-12 जून, उत्तराखंड

मुख्य बातें/अनुशंसाएं

क)	उत्तराखंड की बहु-आपदा जोखिम प्रोफ़ाइल, जिसमें बाढ़, भूस्खलन, बादल फटना, शहरी बाढ़ तथा मानसून से संबंधित अन्य खतरों को शामिल किया गया है, के संबंध में समझ में वृद्धि हुई। इससे जोखिम-सूचित योजना निर्माण एवं आपदा पूर्व तैयारी की आवश्यकता पर बल दिया गया।
ख)	खतरा, जोखिम एवं संवेदनशीलता आकलन, बाढ़-जोखिम क्षेत्रीकरण तथा साक्ष्य-आधारित आपदा प्रबंधन के लिए भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों, उपग्रह उत्पादों एवं उभरते तकनीकी उपकरणों के उपयोग संबंधी क्षमताओं को सुदृढ़ किया गया।
ग)	प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, मौसम पूर्वानुमान उपकरणों तथा जोखिम संचार तंत्रों के संबंध में ज्ञान में वृद्धि हुई, जिससे समयबद्ध तैयारी, प्रभावी प्रतिक्रिया एवं अंतिम छोर तक चेतावनियों के प्रसार को सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।
घ)	मानसून जनित आपात स्थितियों के प्रभावी प्रबंधन हेतु घटना प्रतिक्रिया प्रणाली, आपातकालीन परिचालन केंद्र के कार्यकलापों तथा बहु-एजेंसी समन्वय तंत्रों की समझ को सुदृढ़ किया गया।
ङ)	जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जोखिमों, भूस्खलन शमन उपायों, स्वास्थ्य क्षेत्र की तैयारी, समुदाय-आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा स्थानीय संस्थाओं की आपदा प्रत्यास्थता सुदृढ़ करने में भूमिका के प्रति जागरूकता में वृद्धि हुई।
च)	राहत प्रबंधन, मनोसामाजिक सहयोग, त्वरित क्षति एवं आवश्यकता आकलन तथा समन्वित प्रतिक्रिया योजना निर्माण से संबंधित क्षमताओं को व्यावहारिक अभ्यासों एवं परिदृश्य-आधारित शिक्षण के माध्यम से सुदृढ़ किया गया।

मानसून पूर्व तैयारी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 15-17 जून, पंजाब

मुख्य बातें/अनुशंसाएं

क)	आपदा प्रबंधन में सक्रिय एवं पूर्व तैयारी आधारित दृष्टिकोण के महत्व को सुदृढ़ किया गया, जिसमें प्रभावी बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण के लिए मानसून-पूर्व योजना, जोखिम आकलन तथा पूर्वानुमान आधारित कार्रवाई पर विशेष बल दिया गया।
ख)	पंजाब की बाढ़ जोखिम प्रोफ़ाइल, जिसमें जिला-विशिष्ट संवेदनशीलताएँ, खतरा, अनावृति तथा आपदा तैयारी संबंधी आवश्यकताएँ शामिल हैं, के संबंध में समझ को सुदृढ़ किया गया, जिससे प्रभावी आपदा प्रबंधन योजना निर्माण में सहायता मिलेगी।
ग)	मौसम संबंधी पूर्वानुमानों की व्याख्या करने, प्रारंभिक चेतावनी संबंधी सूचनाओं का प्रभावी उपयोग करने तथा जोखिम पूर्वानुमानों को समयबद्ध पूर्व तैयारी एवं आपदा प्रतिक्रिया उपायों में रूपांतरित करने संबंधी क्षमताओं को सुदृढ़ किया गया।

घ)	बाढ़ संबंधी खतरों के प्रति स्थानीय तैयारी, प्रतिक्रिया क्षमता तथा प्रतिरोधक क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए सामुदायिक सहभागिता, सहभागितापूर्ण योजना निर्माण तथा जन-जागरूकता के महत्व को रेखांकित किया गया।
ङ)	आधुनिक प्रौद्योगिकियों, डेटा-आधारित निर्णय-निर्माण उपकरणों, घटना प्रतिक्रिया प्रणाली तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय तंत्रों के संबंध में ज्ञान को बढ़ाया गया, जिससे आपातकालीन प्रबंधन एवं प्रतिक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।
च)	राहत प्रबंधन, आपदा उपरांत पुनर्प्राप्ति तथा साक्ष्य-आधारित योजना निर्माण के संबंध में गहन समझ विकसित हुई, जिससे बाढ़ की घटनाओं के पश्चात प्रभावी आपदा प्रतिक्रिया, संवेदनशील आबादी की सुरक्षा तथा प्रत्यास्थ पुनर्निर्माण सुनिश्चित करने की क्षमता सुदृढ़ हुई।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय और पत्तन प्राधिकरणों के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 15-18 जून 2026, दिल्ली

मुख्य बातें/अनुशंसाएं

क)	इस कार्यक्रम ने बंदरगाहों के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के संदर्भ में पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय, पत्तन प्राधिकरणों तथा अन्य संबंधित हितधारकों की आवश्यकताओं को प्रभावी रूप से संबोधित किया।
ख)	प्रतिभागियों ने समुद्री क्षेत्र में अग्नि दुर्घटनाओं, साइबर हमलों, नाभिकीय एवं विकिरणीय जोखिमों तथा बहु-आपदा परिदृश्यों सहित खोज एवं बचाव अभियानों के प्रभावी प्रबंधन संबंधी ज्ञान एवं समझ प्राप्त की।
ग)	सहयोगात्मक समूह अभ्यासों के माध्यम से आपदा जोखिम न्यूनीकरण, शमन एवं तैयारी, विभिन्न एजेंसियों की भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों, समन्वय तंत्र, घटना प्रतिक्रिया प्रणाली, आपदा प्रतिक्रिया, पुनर्प्राप्ति, पुनर्निर्माण, व्यवसाय निरंतरता तथा संसाधन तैयार करने जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया गया।
	साथ ही, भारत के समुद्री क्षेत्र के लिए खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता एवं क्षमता विश्लेषण (HRVCA) पद्धतियों में प्रतिभागियों की क्षमता को सुदृढ़ किया गया।
घ)	प्रतिभागियों ने आपदा प्रबंधन की अवधारणाओं, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, विभिन्न योजनाओं तथा प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, बहु-आपदाओं, जलवायु परिवर्तन और उनके पत्तन एवं नौवहन क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभावों की व्यापक समझ विकसित की।
ङ)	समग्र रूप से प्राप्त फीडबैक से यह स्पष्ट हुआ कि प्रशिक्षण की रूपरेखा अत्यंत प्रासंगिक एवं उपयोगी रही, जिसने सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम तथा अनुभवी संसाधन व्यक्तियों के माध्यम से विषयगत अवधारणाओं को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

आपदा शमन वित्त एवं आपदा-प्रतिरोधी अवसंरचना पर प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा एनआईडीएम एवं आईआईएम लखनऊ के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, 22-25 जून 2026, दिल्ली

मुख्य बातें/अनुशंसाएं

क)	आपदा जोखिम वित्तपोषण के ढाँचों तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण, तैयारी, पुनर्प्राप्ति एवं प्रतिरोधक क्षमता निर्माण के पहलों के समर्थन हेतु उपलब्ध वित्तीय तंत्रों की महत्व को रेखांकित किया।
ख)	आपदा शमन निधियों के प्रभावी उपयोग तथा उनसे संबंधित नीतिगत, नियोजन एवं कार्यान्वयन प्रक्रियाओं के संबंध में अधिकारियों के कौशल एवं संस्थागत क्षमताओं को मजबूत किया गया।
ग)	जलवायु प्रत्यास्थता एवं सतत् विकास को सुदृढ़ करने के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण, जोखिम वित्तपोषण तथा बीमा तंत्रों
	के एकीकरण संबंधी समझ में वृद्धि हुई।
घ)	आपदा जोखिम वित्तपोषण के विभिन्न साधनों तथा आपदा तैयारी, प्रतिक्रिया, पुनर्प्राप्ति एवं जोखिम प्रबंधन में वित्तीय संस्थानों की भूमिका के संबंध में ज्ञान को सुदृढ़ किया गया।
ङ)	आपदा जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन तथा दीर्घकालिक विकास नियोजन के लिए आपदा-रोधी अवसंरचना के महत्व को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में एकीकृत किया गया।

आपदा शमन एवं शमन निधि पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 22-25 जून 2026, दिल्ली

मुख्य बातें/अनुशंसाएं

क)	जोखिम के प्रति सतर्क विकास नियोजन के लिए आपदा शमन रूपरेखाओं, नीतियों तथा वित्तपोषण तंत्रों की आवश्यकता पर बल दिया गया।
ख)	शमन परियोजना प्रस्तावों तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों की तैयारी, मूल्यांकन एवं कार्यान्वयन संबंधी क्षमताओं को सुदृढ़ किया गया।
ग)	आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी पहलों के लिए राष्ट्रीय आपदा शमन निधि एवं राज्य आपदा शमन निधि के प्रभावी उपयोग के संबंध में बेहतर ज्ञान एवं समझ प्राप्त हुई।
घ)	विभिन्न क्षेत्रों की विकास योजनाओं तथा अवसंरचना परियोजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं शमन उपायों के एकीकरण के महत्व को रेखांकित किया गया।
ङ)	प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से शमन कार्यक्रमों की योजना, निगरानी, मूल्यांकन एवं प्रभावी कार्यान्वयन हेतु संस्थागत क्षमताओं को और अधिक सुदृढ़ किया गया।

आमने-सामने प्रशिक्षण कार्यक्रम

एनआईडीएम दक्षिणी परिसर

आपदा जोखिम प्रबंधन पर 15वां समग्र पाठ्यक्रम, 06-17 अप्रैल 2026, आंध्र प्रदेश

मुख्य बातें/अनुशंसाएं

क)	जोखिम सूचित योजना एवं निर्णय-निर्माण को सुदृढ़ करने के लिए आपदा जोखिम प्रबंधन की अवधारणाओं, जैसे- खतरे, संवेदनशीलता, जोखिम-उन्मुखता, प्रत्यास्थता तथा आपदा प्रबंधन चक्र की समझ में वृद्धि हुई।
ख)	आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रत्यास्थता निर्माण को समर्थन प्रदान करने वाली राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय आपदा प्रबंधन रूपरेखाओं, संस्थागत तंत्रों तथा विधिक प्रावधानों के संबंध में ज्ञान को सुदृढ़ किया गया।
ग)	खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता एवं क्षमता आकलन (HRVCA), जलवायु जोखिम विश्लेषण तथा आपदा तैयारी एवं शमन हेतु भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों और प्रारंभिक चेतावनी के उपयोग संबंधी क्षमताओं में वृद्धि हुई।
घ)	तैयारी, आपदा प्रतिक्रिया, सामुदायिक आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा समावेशी दृष्टिकोणों की समझ को सुदृढ़ किया गया, जिससे स्थानीय प्रत्यास्थता एवं आपातकालीन प्रबंधन प्रणालियों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।
ङ)	आपातकालीन प्रतिक्रिया, मनोसामाजिक सहायता, औद्योगिक एवं तकनीकी खतरों तथा आपदा पश्चात् पुनर्प्राप्ति योजना से संबंधित व्यावहारिक ज्ञान को सुदृढ़ किया गया, जिसमें 'बिल्ड बैक बेटर' दृष्टिकोण को भी शामिल किया गया।
च)	आपदा जोखिम वित्तपोषण तंत्रों तथा विकास नियोजन प्रक्रियाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के एकीकरण संबंधी समझ को बेहतर बनाया गया, जिससे सुदृढ़ समुदायों एवं अवसंरचना के निर्माण को बढ़ावा मिल सके।

ग्राम पंचायत विकास योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के एकीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 27-30 अप्रैल 2026, आंध्र प्रदेश

मुख्य बातें/अनुशंसाएं

क)	आपदा जोखिम न्यूनीकरण की अवधारणाओं, संस्थागत रूपरेखाओं तथा आपदा-रोधी ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका के समन्वय के संबंध में समझ को सुदृढ़ किया गया।
ख)	जोखिम-सूचित एवं सहभागी नियोजन दृष्टिकोणों के माध्यम से ग्राम पंचायत विकास योजनाओं में आपदा जोखिम संबंधी विचारों के एकीकरण हेतु प्रतिभागियों की क्षमताओं को सशक्त बनाया गया।
ग)	स्थानीय जोखिमों, उपलब्ध संसाधनों तथा प्रत्यास्थता उपायों की पहचान के लिए सामुदायिक-आधारित दृष्टिकोणों सहित खतरा, संवेदनशीलता एवं जोखिम आकलन उपकरणों के संबंध में ज्ञान में वृद्धि हुई।
घ)	प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, संचार प्रौद्योगिकियों, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा आपदा जोखिमों को कम करने एवं सामुदायिक प्रत्यास्थता को सुदृढ़ करने में उनकी भूमिका के प्रति जागरूकता में वृद्धि हुई।
ङ)	सामुदायिक-आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन की समझ को सुदृढ़ किया गया, जिसमें स्थानीय संस्थाओं, स्वयंसेवकों, स्वयं सहायता समूहों तथा नागरिकों की आपदा तैयारी एवं प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका पर विशेष बल दिया गया।
च)	ग्राम आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी, आपदा जोखिम न्यूनीकरण का ग्रामीण विकास योजनाओं के साथ अभिसरण सुनिश्चित करने तथा सुदृढ़ एवं सतत् स्थानीय विकास को बढ़ावा देने संबंधी व्यावहारिक कौशल में वृद्धि हुई।

तेलंगाना सरकार के डिप्टी कलेक्टर प्रशिक्षुओं के लिए आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 09-10 मई 2026, आंध्र प्रदेश

मुख्य बातें/अनुशंसाएं

क)	आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, संस्थागत रूपरेखाओं तथा आपदा जोखिम एवं प्रत्यास्थता को सुदृढ़ करने में जिला प्रशासन की भूमिका के संबंध में समझ को और अधिक विकसित किया गया।
ख)	प्रभावी आपदा तैयारी एवं जोखिम न्यूनीकरण के लिए खतरा, जोखिम एवं संवेदनशीलता आकलन, संसाधन मानचित्रण तथा जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी संबंधी क्षमताओं को सुदृढ़ किया गया।
ग)	साक्ष्य-आधारित निर्णय-निर्माण एवं आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों, उपग्रह आँकड़ों, ड्रोन, खतरा मानचित्रण तथा अन्य उभरते तकनीकी उपकरणों के उपयोग संबंधी ज्ञान में वृद्धि हुई।
घ)	मौसम पूर्वानुमान, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, पूर्वानुमानों की व्याख्या तथा अंतिम छोर तक सूचना प्रसार तंत्रों की समझ को सुदृढ़ किया गया, जिससे समयबद्ध तैयारी एवं प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके।
ङ)	प्रतिभागियों ने आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान घटना प्रतिक्रिया प्रणाली, आपातकालीन परिचालन केंद्र के संचालन, खोज एवं बचाव कार्यों, संसाधन प्रबंधन तथा विभिन्न एजेंसियों के मध्य समन्वय के संबंध में विशेषज्ञता एवं व्यावहारिक दक्षता अर्जित की।
च)	नेतृत्व क्षमता, सामुदायिक सहभागिता, आपदा उपरांत पुनर्प्राप्ति, क्षति आकलन, पुनर्वास योजना तथा सुदृढ़ पुनर्निर्माण के क्षेत्रों में क्षमताओं को मजबूत किया गया, जिससे सतत् एवं जोखिम के प्रति सजग रहते हुए विकास कार्यों में सहयोग दिया जा सके।

प्रथम मास्टर प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम, 11-22 मई 2026, आंध्र प्रदेश

मुख्य बातें/अनुशंसाएं

क)	राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा जिला स्तर पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं क्षमता निर्माण पहलों को प्रभावी समर्थन प्रदान करने हेतु प्रशिक्षित मास्टर प्रशिक्षकों के एक सुदृढ़ समूह के विकास की क्षमताओं को विकसित किया।
ख)	आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण अभिकल्पना (Training Design), प्रशिक्षण प्रदान करने की पद्धतियों तथा प्रभावी क्षमता विकास दृष्टिकोणों की व्यापक समझ प्राप्त हुई।
ग)	आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण पहलों की गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता को बढ़ाने में पेशेवर विशेषज्ञता तथा मानकीकृत प्रशिक्षण सामग्रियों एवं प्रक्रियाओं के महत्व पर बल दिया गया।
घ)	प्रशिक्षित मास्टर प्रशिक्षकों की प्रभावी तैनाती एवं उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की ओर से अधिक सुदृढ़ संस्थागत प्रतिबद्धता की आवश्यकता को उजागर किया गया।
ङ)	प्रशिक्षित पेशेवरों की दीर्घकालिक सहभागिता तथा क्षमता विकास को समर्थन प्रदान करने हेतु सतत् वित्तीय एवं संस्थागत तंत्रों के महत्व पर विशेष बल दिया गया।

हीट वेव एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 18-22 मई 2026, आंध्र प्रदेश

मुख्य बातें/अनुशंसाएं

क)	बदलती जलवायु परिस्थितियों के कारण बढ़ती आवृत्ति के साथ उभर रही लू (हीट वेव) को एक प्रमुख जलवायु-प्रेरित आपदा के रूप में रेखांकित किया गया। साथ ही, इसके कारणों, विशेषताओं, प्रभावों तथा बदलती जलवायु के परिप्रेक्ष्य में इसकी बढ़ती घटनाओं के संबंध में समझ को सुदृढ़ किया गया
ख)	लू से संबंधित जनस्वास्थ्य जोखिमों, निवारक उपायों, आपातकालीन प्रतिक्रिया तथा लू-जनित बीमारियों के प्रभावी प्रबंधन के संबंध में ज्ञान एवं समझ को सुदृढ़ किया गया, जिससे कि स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जा सके।
ग)	लू के संबंध में प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, पूर्वानुमान तंत्रों, जोखिम संचार तथा अंतिम छोर तक सूचना पहुंचाने के उपाय की रणनीतियों की समझ को बेहतर बनाया गया, जिससे समयबद्ध तैयारी एवं प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके।
घ)	साक्ष्य-आधारित नियोजन को बढ़ावा देने तथा संवेदनशीलता को कम करने के लिए लू कार्य योजनाओं की तैयारी एवं क्रियान्वयन तथा ताप जोखिम आकलन संबंधी क्षमताओं को सुदृढ़ किया गया।
ङ)	लू के विश्लेषण, पूर्वानुमान तथा पूर्व तैयारी आधारित योजना निर्माण के लिए भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों, मौसम विज्ञान निगरानी प्रणालियों तथा आँकड़ा-आधारित (डेटा-संचालित) दृष्टिकोणों के एकीकरण के संबंध में ज्ञान एवं समझ को सुदृढ़ किया गया।
च)	लू के प्रति प्रत्यास्थता को बढ़ाने हेतु शीतल छतों, शहरी हरियाली, जल संरक्षण तथा जलवायु-अनुकूल अवसंरचना सहित संरचनात्मक एवं गैर-संरचनात्मक शमन उपायों को अपनाने पर बल दिया गया।

आपदा जोखिम प्रबंधन पर 17वां समग्र पाठ्यक्रम, 08-19 जून 2026, आंध्र प्रदेश

मुख्य बातें/अनुशंसाएं

क)	प्रतिभागियों ने आपदा प्रबंधन चक्र, संस्थागत ढांचे और आपदा के असर को ध्यान में रखकर अपनाए जाने वाले तरीकों की व्यापक समझ विकसित की, जिससे कि आपदा से निपटने की व्यवस्था को प्रभावी बनाया जा सके और आपदा का सामना करने की क्षमता बढ़ाई जा सके।
ख)	खतरे, जोखिम, संवेदनशीलता और क्षमता के आकलन के बारे में व्यावहारिक जानकारी दी गई; साथ ही, सबूतों पर आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, सचेत, आईडीआरएन और एनडीएमआईएस के इस्तेमाल के बारे में भी बताया गया।
ग)	विशेषज्ञों के साथ संवाद, केस स्टडी, समूह अभ्यास, फील्ड विज़िट, तथा अनुभव-साझा करने से विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय, आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र, मौसम पूर्वानुमान तथा समुदाय-आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण के संबंध में गहन समझ विकसित हुई, जिससे आपदा जोखिम प्रबंधन के प्रति विभिन्न विषयों के संबंध में नई दृष्टिकोण विकसित हुई।
घ)	चक्रवात एवं बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में आपदा जोखिमों को कम करने के लिए संकट आकलन, सामुदायिक सुदृढ़ता तथा प्रकृति-आधारित समाधानों के महत्व को रेखांकित किया गया।
ङ)	जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, जनस्वास्थ्य आपातस्थितियाँ, मनोसामाजिक देखभाल, समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण, आपदा जोखिम वित्तपोषण तथा स्थायी पुनर्वास के लिए 'बिल्ड बैक बेटर' दृष्टिकोण सहित विभिन्न अहम विषयों पर व्यापक दृष्टिकोण एवं समग्र समझ विकसित हुई।
च)	प्रशिक्षण कार्यक्रम ने आपदा प्रबंधन की व्यापक समझ प्रदान की तथा जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य आपातस्थितियाँ, मनोसामाजिक सहायता, समावेशी दृष्टिकोण (किसी को भी पीछे न छोड़ना), जोखिम वित्तपोषण, 'बिल्ड बैक बेटर' सिद्धांत तथा सामुदायिक-आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण जैसे अंतर्विषयक मुद्दों को भी प्रभावी रूप से संबोधित किया।

सम्मेलन/कार्यशाला/सेमिनार/परामर्श बैठक

पीएचईडीएम पेशेवरों के लिए नेतृत्व और प्रबंधन रणनीतियों पर वेबिनार, 24 अप्रैल 2026, दिल्ली

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र तथा यू.एस. सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी)-इंडिया के सहयोग से 'आपदा प्रबंधन में सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियाँ (पीएचईडीएम) पेशेवरों के लिए नेतृत्व एवं प्रबंधन रणनीतियाँ' विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया। इस वेबिनार का उद्देश्य जनस्वास्थ्य आपातकाल एवं आपदा प्रबंधन से जुड़े पेशेवरों की नेतृत्व क्षमताओं, संकट प्रबंधन कौशल, टीम अभिप्रेरणा तथा प्रभावी संचार रणनीतियों को सुदृढ़ करना था। वेबिनार के दौरान हुई चर्चाओं में अनुकूलनशील नेतृत्व, अनिश्चित परिस्थितियों में निर्णय-निर्माण तथा आपातकालीन स्थितियों के दौरान संगठनात्मक प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए व्यावहारिक प्रबंधन उपकरणों के महत्व पर विशेष बल दिया गया। इस कार्यक्रम ने जनस्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन क्षेत्र के विशेषज्ञों और व्यावसायिकों के बीच ज्ञान एवं अनुभवों के आदान-प्रदान के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान किया तथा प्रभावी आपातकालीन तैयारी एवं प्रतिक्रिया के लिए संस्थागत क्षमताओं को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

जलवायु-अनुकूल एवं सुदृढ़ राजमार्गों हेतु बहु-आपदा जोखिम आकलन पर परामर्शी बैठक, 06 अप्रैल 2026, दिल्ली

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सहयोग से, एनआईडीएम ने जलवायु-अनुकूल और मज़बूत राजमार्गों के लिए 'मल्टी-हैज़र्ड रिस्क असेसमेंट' (एमएचआरए) पर एक परामर्श बैठक आयोजित की। साथ ही, राष्ट्रीय राजमार्ग जलवायु अनुकूलन नीति और दिशा-निर्देश भी तैयार किए गए। परियोजना निदेशक, हाईकैप ने अपने संबोधन में बताया कि बैठक का उद्देश्य परियोजना की प्रगति की समीक्षा करना तथा प्रमुख परियोजना दस्तावेजों को अंतिम रूप प्रदान करना था। विचार-विमर्श के दौरान सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से प्राप्त सुझावों को सम्मिलित करते हुए समेकित बहु-आपदा जोखिम आकलन प्रतिवेदन की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। एनआईडीएम की टीम, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों, विषय-विशेषज्ञों तथा परियोजना संघ के भागीदारों ने जोखिम आकलन रूपरेखा में जलवायु प्रक्षेपण आँकड़ों तथा परिवहन आपातकालीन प्रबंधन योजना- यातायात निकासी योजना (TEMP-TEP) एवं लागत-लाभ विश्लेषण प्रतिवेदनों के अद्यतन निष्कर्षों के समावेशन पर विचार-विमर्श किया। बैठक में व्यापक क्षमता एवं प्रत्यास्थता आकलन की आवश्यकता तथा राजमार्ग के विभिन्न खंडों के लिए विशिष्ट अनुकूलन एवं प्रत्यास्थता रणनीतियों के विकास पर भी विशेष बल दिया गया। यह सहमति बनी कि समेकित प्रतिवेदनों को प्रत्येक भौगोलिक-भूरूपीय क्षेत्र के लिए पृथक खंडों के रूप में तैयार किया जाएगा।

संहिताओं एवं नियमावलियों की समीक्षा पर परामर्श बैठक, 20 अप्रैल 2026, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, दिल्ली

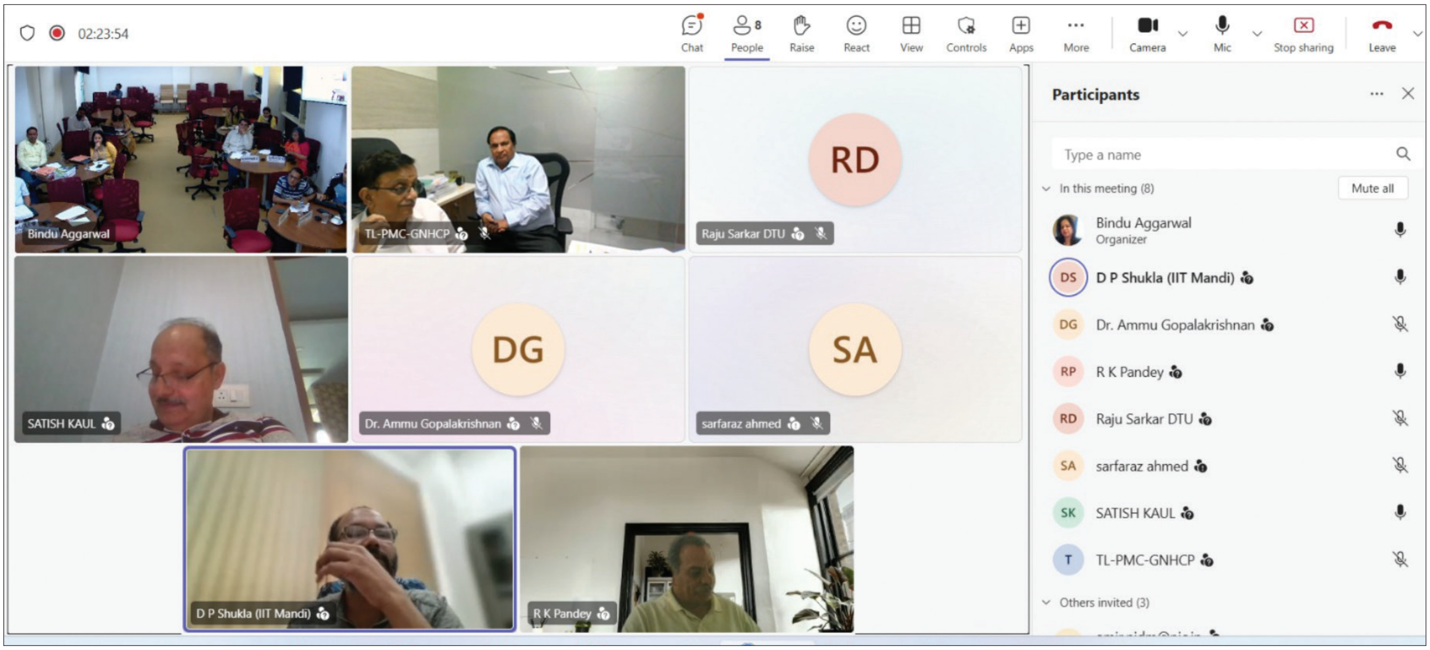

हाईकैप परियोजना के अंतर्गत राजमार्गों से संबंधित वर्तमान संहिताओं एवं नियमावलियों की समीक्षा के उद्देश्य से 20 अप्रैल 2026 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में हाइब्रिड माध्यम से एक परामर्शी बैठक आयोजित की गई।

बैठक के दौरान चयनित भारतीय सड़क कांग्रेस की संहिताओं एवं नियमावलियों की विस्तृत समीक्षा की गई, जिससे कि यह आकलन किया जा सके कि वे जलवायु प्रत्यास्थता तथा राजमार्ग अवसंरचना के समक्ष उभरती चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने में कितनी सक्षम हैं। विचार-विमर्श में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय सड़क कांग्रेस तथा अन्य विषय-विशेषज्ञों ने भाग लिया। चर्चा का मुख्य उद्देश्य बदलती जलवायु परिस्थितियों के संदर्भ में विद्यमान कमियों की पहचान करना, नई प्रौद्योगिकियों को समाहित करना तथा कार्यान्वयन प्रक्रियाओं को अधिक सुदृढ़ बनाना था।

बैठक में यह भी रेखांकित किया गया कि वर्तमान संहिताओं एवं नियमावलियों के ढाँचे में नवोन्मेषी सामग्रियों, प्रदर्शन-आधारित दृष्टिकोणों, डिजिटल प्रौद्योगिकियों तथा जलवायु-प्रत्यास्थ अभिकल्पना सिद्धांतों (Climate-Resilient Design Principles) का समावेश किया जाना आवश्यक है। प्रत्येक संहिता के संबंध में उसके भावी संशोधन एवं अद्यतन के लिए विस्तृत टिप्पणियाँ एवं अनुशंसाएँ प्रस्तुत की गईं।

बैठक का समापन उन विशिष्ट संहिताओं के संबंध में अनुशंसाओं के साथ हुआ जिनमें संशोधन की आवश्यकता है। साथ ही, उभरती प्रौद्योगिकियों, जलवायु संबंधी विचारों तथा क्षेत्रीय अनुभवों से प्राप्त शिक्षाओं को उनमें शामिल करने पर बल दिया गया। वहीं, हाल ही में अद्यतन की गई कुछ संहिताओं को पर्याप्त एवं प्रासंगिक पाया गया तथा वर्तमान चरण में उनके संशोधन की आवश्यकता नहीं मानी गई।

संहिताओं एवं नियमावलियों की समीक्षा के निष्कर्षों पर विचार-विमर्श हेतु परामर्शी कार्यशाला, 21 मई 2026, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, दिल्ली

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सहयोग से संचालित 'राष्ट्रीय राजमार्ग जलवायु अनुकूलन नीति एवं दिशा-निर्देशों के विकास' परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा 21 मई 2026 को 'संहिताओं एवं नियमावलियों की समीक्षा' विषय पर एक परामर्शी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में भारतीय सड़क कांग्रेस, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा अन्य सरकारी एवं तकनीकी संस्थानों के विशेषज्ञों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना को संचालित करने वाली वर्तमान संहिताओं, मानकों, नियमावलियों एवं दिशा-निर्देशों की पर्याप्तता और प्रासंगिकता की समीक्षा करना था। कार्यशाला ने राजमार्गों की योजना, अभिकल्पना, निर्माण, संचालन तथा अनुरक्षण प्रक्रियाओं में जलवायु प्रत्यास्थता एवं अनुकूलन संबंधी विचारों के एकीकरण पर चर्चा के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान किया। विचार-विमर्श का केंद्र बिंदु वर्तमान भारतीय सड़क कांग्रेस की संहिताओं एवं नियमावलियों की समीक्षा से प्राप्त निष्कर्ष रहे, जिन्हें बाढ़, भूस्खलन, अत्यधिक वर्षा,लू, चक्रवात तथा अपरदन जैसे बढ़ते जलवायु-जनित जोखिमों के संदर्भ में परखा गया। कार्यशाला में सम्मिलित विशेषज्ञों ने फुटपाथ तथा पुलों से संबंधित चयनित संहिताओं में चिन्हित कमियों को रेखांकित किया तथा राजमार्ग अवसंरचना की प्रत्यास्थता एवं दीर्घकालिक स्थिरता को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक उपायों की अनुशंसा की। यद्यपि अधिकांश आईआरसी संहिताएँ तकनीकी दृष्टि से पर्याप्त पाई गईं, तथापि वर्तमान प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वयन, निगरानी, प्रवर्तन तथा अनुपालन तंत्रों को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया।

'राष्ट्रीय राजमार्ग जलवायु अनुकूलन नीति रूपरेखा' पर विचार-विमर्श हेतु परामर्शी कार्यशाला 21 मई 2026, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, दिल्ली

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सहयोग से संचालित 'राष्ट्रीय राजमार्ग जलवायु अनुकूलन नीति एवं दिशा-निर्देशों के विकास' परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा 21 मई 2026 को 'राष्ट्रीय राजमार्ग जलवायु अनुकूलन नीति रूपरेखा' विषय पर एक परामर्शी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इस कार्यशाला में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय सड़क कांग्रेस, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा अन्य सरकारी एवं तकनीकी संस्थानों के विशेषज्ञों एवं हितधारकों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्देश्य प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग जलवायु अनुकूलन नीति रूपरेखा तथा राजमार्ग क्षेत्र में जलवायु प्रत्यास्थता को मुख्यधारा में शामिल करने में इसकी भूमिका पर विचार-विमर्श करना था।

नीति विशेषज्ञ द्वारा प्रारंभिक मसौदा प्रस्तुत किया गया, जिसमें नीति की परिकल्पना, मार्गदर्शक सिद्धांतों, रणनीतिक प्राथमिकताओं, संस्थागत व्यवस्थाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना को प्रभावित करने वाले वर्तमान एवं उभरते जलवायु जोखिमों से निपटने के लिए आवश्यक कार्यान्वयन तंत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। अन्य विशेषज्ञों ने अनुकूलन क्षमता को सुदृढ़ करने, जोखिम-सूचित निर्णय-निर्माण को बढ़ावा देने तथा भविष्य की जलवायु अनिश्चितताओं एवं चरम मौसमीय घटनाओं के विरुद्ध भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की दीर्घकालिक प्रत्यास्थता एवं स्थिरता को बढ़ाने हेतु प्रमुख चुनौतियों, अवसरों एवं प्राथमिक कार्यों पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए।

कार्यशाला में यह भी रेखांकित किया गया कि प्रस्तावित नीति रूपरेखा 30 चयनित संवेदनशील राजमार्ग खंडों पर किए गए विस्तृत तकनीकी अध्ययनों का परिणाम है। इन अध्ययनों में जोखिम आकलन, जलवायु प्रक्षेपण, लागत-लाभ विश्लेषण, परिवहन आपातकालीन प्रबंधन एवं यातायात निकासी योजना तथा अभियांत्रिकी-आधारित प्रत्यास्थता आकलन शामिल हैं।

कार्यशाला में इस बात पर बल दिया गया कि राजमार्ग क्षेत्र में जलवायु संबंधी जोखिमों एवं संवेदनशीलताओं का व्यवस्थित समाधान सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक, दूरदर्शी एवं समग्र राष्ट्रीय राजमार्ग जलवायु अनुकूलन नीति रूपरेखा की आवश्यकता है। विचार-विमर्श के दौरान बदलती जलवायु परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना की दीर्घकालिक स्थिरता, सुरक्षा एवं प्रत्यास्थता सुनिश्चित करने हेतु सक्रिय अनुकूलन उपायों को अपनाने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया गया।

दक्षिण-पश्चिम मानसून 2026 पूर्वानुमान-तैयारी एवं बहु-आपदा मौसम चेतावनी सेवाएँ विषय पर हितधारकों की बैठक, 02 जून 2026, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश

दक्षिण-पश्चिम मानसून 2026 पूर्वानुमान-तैयारी एवं बहु-आपदा मौसम चेतावनी सेवाएँ विषय पर एक हितधारक बैठक का आयोजन एनआईडीएम के दक्षिणी परिसर, विजयवाड़ा में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आगामी मानसून ऋतु के लिए तैयारी को सुदृढ़ करना तथा प्रमुख हितधारकों के बीच समन्वय को बढ़ावा देना था।

कार्यक्रम के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून 2026 के पूर्वानुमान, मौसम एवं जलवायु सेवाओं, चक्रवात तैयारी तथा बहु-आपदा प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा की गईं। विचार-विमर्श के दौरान प्रभाव-आधारित पूर्वानुमान, चेतावनियों के समयबद्ध प्रसार तथा सूचित निर्णय-निर्माण के लिए आधुनिक मौसम विज्ञान प्रौद्योगिकियों के उपयोग के महत्व पर विशेष बल दिया गया।

चर्चाओं में आपदा प्रबंधन एजेंसियों, विभिन्न विभागों, मीडिया संगठनों तथा स्थानीय प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता को भी रेखांकित किया गया, ताकि आपदा तैयारी एवं प्रतिक्रिया तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। कार्यक्रम में क्षेत्र-विशिष्ट तैयारी योजनाओं, समुदाय-केंद्रित जोखिम संचार तथा प्रारंभिक चेतावनी सेवाओं के प्रभावी उपयोग के महत्व को पुन: स्थापित किया गया, जिससे आपदाओं के प्रभावों को न्यूनतम करने तथा समुदायों की प्रत्यास्थता को सुदृढ़ करने में सहायता मिल सके।

‘बहु-आपदा मॉडलिंग प्रतिवेदनों’ पर परामर्शी कार्यशाला, 10 जून 2026, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, दिल्ली

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा ‘राष्ट्रीय राजमार्ग जलवायु अनुकूलन नीति एवं दिशा-निर्देशों के विकास’ परियोजना के अंतर्गत 10 जून 2026 को बहु-आपदा मॉडलिंग प्रतिवेदनों पर एक परामर्शी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, आईआईटी मंडी, दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उत्तर-पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर, पांडिचेरी विश्वविद्यालय, आरएमएसआई तथा अन्य हितधारक संस्थाओं के विशेषज्ञों एवं प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह कार्यशाला भारत के विभिन्न जलवायु एवं भौगोलिक-भूरूपीय क्षेत्रों को आच्छादित करने वाले 30 चयनित राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों पर किए गए बहु-आपदा मॉडलिंग अध्ययनों की समीक्षा एवं प्रमाणीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण मंच सिद्ध हुई। परियोजना संघ के भागीदारों ने खतरा आकलन, जलवायु प्रक्षेपण, संवेदनशीलता मानचित्रण तथा जोखिम विश्लेषण से संबंधित अध्ययन निष्कर्ष प्रस्तुत किए। समीक्षकों एवं विषय-विशेषज्ञों ने अध्ययन की कार्यप्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा जलवायु-प्रत्यास्थ राजमार्ग नियोजन, नीति निर्माण एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण में इसकी उपयोगिता को बढ़ाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण तकनीकी सुझाव एवं परामर्श प्रदान किए।

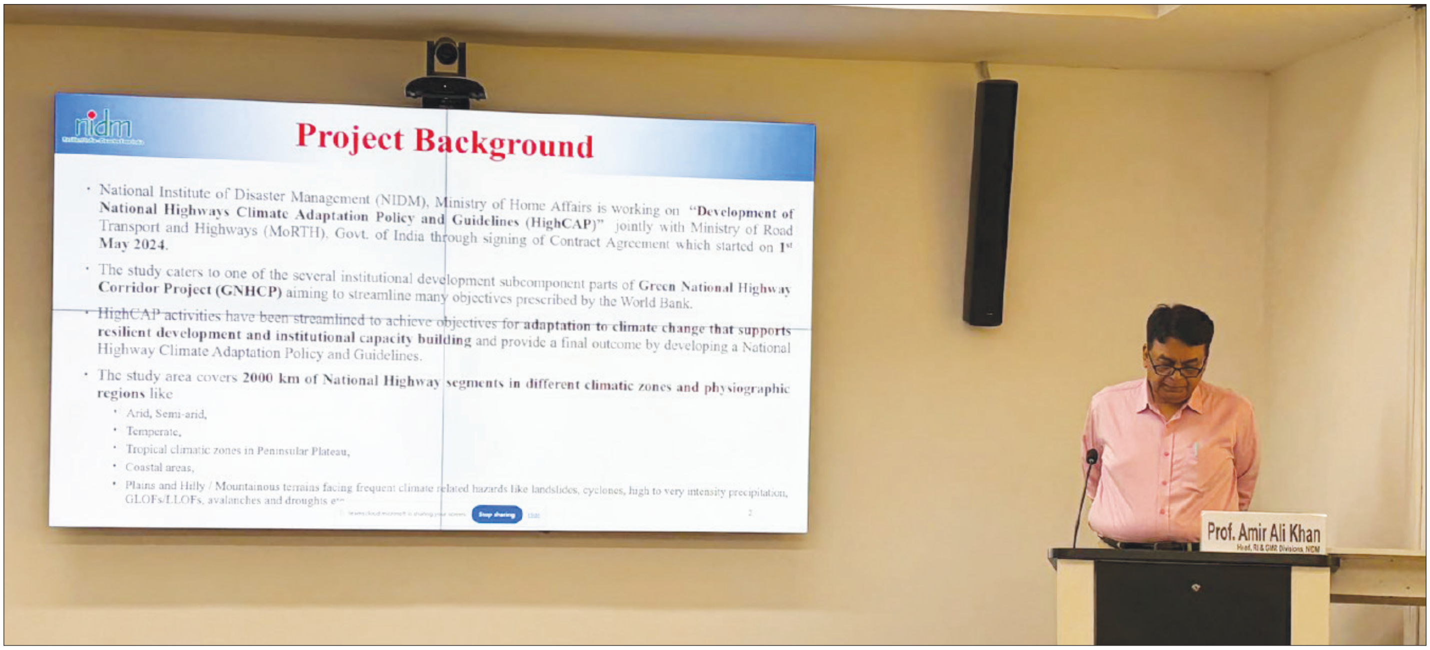

पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम, 18–19 मई 2026, श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने जम्मू एवं कश्मीर सरकार के आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण विभाग के सहयोग से 'पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम' का दो दिवसीय आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बहु-आपदा परिदृश्यों में आपदा उपरांत पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण नियोजन के लिए संस्थागत क्षमताओं को सुदृढ़ करना था।

कार्यक्रम के दौरान पुनर्प्राप्ति रूपरेखाओं, पुनर्निर्माण नियोजन की कार्यप्रणालियों, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के सिद्धांतों तथा प्रत्यास्थता निर्माण संबंधी दृष्टिकोणों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम ने प्रतिभागियों को पुनर्प्राप्ति एवं पुनर्निर्माण पहलों के लिए संस्थागत तंत्रों तथा कार्यान्वयन रणनीतियों से संबंधित व्यावहारिक जानकारी प्रदान की। साथ ही, विकास योजनाओं में आपदा प्रत्यास्थता को समाहित करने की आवश्यकता एवं महत्व पर विशेष बल दिया गया।

साइबर सुरक्षा जागरूकता पर कार्यशाला, 20 मई 2026, दिल्ली

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मध्य साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्मों के सुरक्षित उपयोग, साइबर स्वच्छता, पहचान की चोरी की रोकथाम, मोबाइल एवं बैंकिंग सुरक्षा तथा सोशल इंजीनियरिंग आधारित खतरों से बचाव जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

विचार-विमर्श के दौरान सुरक्षित इंटरनेट ब्राउजिंग प्रथाओं, साइबर घटनाओं की रिपोर्टिंग व्यवस्था तथा साइबर जोखिमों के प्रति संस्थागत तैयारी के महत्व पर विशेष बल दिया गया। कार्यशाला ने सतत् जागरूकता, सतर्कता एवं साइबर सुरक्षा की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाकर एक डिजिटल रूप से मजबूत कार्य वातावरण विकसित करने की आवश्यकता को पुन: रेखांकित किया।

समुदाय आधारित जनस्वास्थ्य आपातकाल एवं आपदा प्रबंधन (सीबी-पीएचईडीएम) टियर-।। पायलट कार्यक्रम, 20–21 मई 2026, सुपौल, बिहार

सामुदायिक आधारित जनस्वास्थ्य आपातकाल एवं आपदा प्रबंधन टियर-।। पायलट कार्यक्रम का आयोजन बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सुपौल, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र तथा CDC-India के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य जनस्वास्थ्य आपातकालीन स्थितियों एवं आपदाओं के प्रति समुदाय स्तर पर तैयारी और प्रभावी प्रतिक्रिया क्षमता को सुदृढ़ करना था। इस कार्यक्रम में अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की क्षमताओं के विकास पर विशेष बल दिया गया। इसके अंतर्गत जनस्वास्थ्य आपातकाल प्रबंधन, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (CPR), जीवनरक्षक तकनीकों तथा अग्नि सुरक्षा उपायों से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया गया। संवादात्मक शिक्षण पद्धतियों, जन-जागरूकता गतिविधियों तथा व्यावहारिक प्रदर्शन के माध्यम से प्रतिभागियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की गई तथा उनके ज्ञान और कौशल को सुदृढ़ किया गया।

कार्यक्रम ने सामुदायिक आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन के महत्व को रेखांकित किया तथा जमीनी स्तर पर समुदायों की प्रत्यास्थता और जनस्वास्थ्य आपातकालीन तैयारी को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

आईएएस प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए आपदा प्रबंधन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर अभिमुखीकरण कार्यक्रम, 23 मई 2026, दिल्ली

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा वर्ष 2024 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए आपदा प्रबंधन एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण विषय पर एक दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य उभरते हुए आपदा जोखिमों, प्रत्यास्थ शासन (Resilient Governance) तथा संस्थागत तैयारी के संबंध में प्रशिक्षुओं की समझ को सुदृढ़ करना था। कार्यक्रम में आपदा जोखिम न्यूनीकरण की बदलती प्रवृत्तियों, प्रौद्योगिकी-सक्षम आपदा प्रबंधन, प्रत्यास्थ पुनर्प्राप्ति तथा बाढ़, चक्रवात और भूकंप जैसी विशिष्ट आपदाओं के लिए तैयारी से संबंधित विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। तकनीकी सत्रों में सक्रिय जोखिम शासन, विकास नियोजन में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के एकीकरण तथा प्रत्यास्थता निर्माण में प्रौद्योगिकी और नवाचार की भूमिका पर विशेष बल दिया गया।

यह कार्यक्रम भावी प्रशासकों को आपदा जोखिम प्रबंधन तथा प्रत्यास्थ विकास की अवधारणाओं को गहराई से समझने और उन्हें प्रभावी प्रशासनिक कार्यप्रणाली में समाहित करने हेतु एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करने में सफल रहा।

भारत आपदा संसाधन नेटवर्क (आईडीआरएन) पर राष्ट्रीय कार्यशाला, 29 मई 2026, दिल्ली

हिमालयी राज्यों के लिए भारत आपदा संसाधन नेटवर्क (IDRN) के संचालन एवं उपयोगिता विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला में आपदा तैयारी, आपदा प्रतिक्रिया तथा संसाधन प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने में डिजिटल प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकी-सक्षम प्रणालियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर विशेष बल दिया गया। कार्यशाला में आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान प्रभावी संसाधन सूची प्रबंधन, संसाधनों के त्वरित जुटान तथा विभिन्न एजेंसियों के मध्य बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए IDRN प्लेटफॉर्म के प्रभावी उपयोग के महत्व को रेखांकित किया गया। विचार-विमर्श के दौरान साक्ष्य-आधारित निर्णय-निर्माण को सुदृढ़ करने के लिए आपदा संसाधनों से संबंधित वर्गीकृत एवं नियमित रूप से अद्यतन आँकड़ों को मुख्यधारा में शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। प्रतिभागियों ने परिस्थितिजन्य जागरूकता तथा परिचालन दक्षता को बढ़ाने के लिए वास्तविक समय की भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों और डिजिटल उपकरणों के एकीकरण पर भी विस्तार से चर्चा की।

कार्यशाला में आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों एवं कार्मिकों के सतत् क्षमता निर्माण तथा राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर की एजेंसियों के बीच सहयोग और समन्वय को और अधिक सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया। समग्र रूप से, इस कार्यक्रम ने डिजिटल आपदा प्रबंधन प्लेटफॉर्मों के प्रभावी उपयोग, प्रौद्योगिकी-संचालित सुशासन तथा समन्वित संस्थागत तंत्र के माध्यम से आपदा-रोधी भारत के निर्माण की परिकल्पना को और अधिक सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

विशेषज्ञ समीक्षा समिति की प्रथम बैठक, 05 जून 2026, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, दिल्ली परिसर (हाइब्रिड माध्यम)

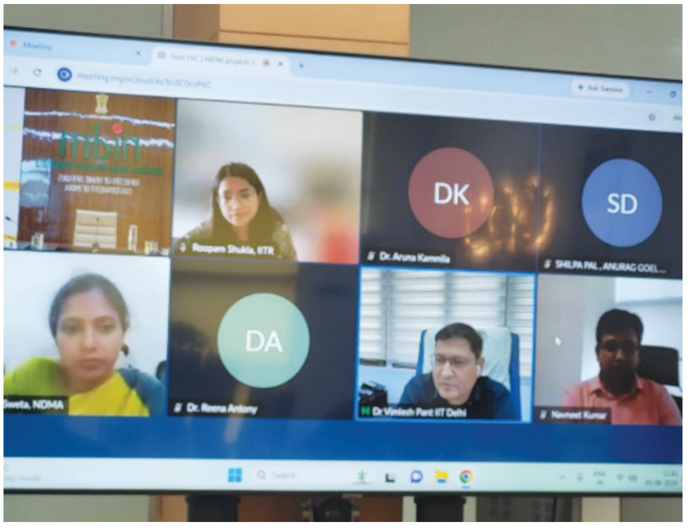

वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान अनुसंधान परियोजना/अध्ययन : कार्य एवं नवाचार अनुसंधान के लिए चयनित परियोजनाओं की विशेषज्ञ समीक्षा समिति की प्रथम बैठक दिनांक 05.06.2026 को आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रो. आमिर अली खान, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, समुत्थानशील अवसंरचना प्रभाग, एनआईडीएम द्वारा की गई। समिति में बाह्य विशेषज्ञों के रूप में डॉ. श्वेता बैद्य, वरिष्ठ परामर्शदाता, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा प्रो. विमलेश पंत, प्रोफेसर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली सम्मिलित हुए। बैठक का मुख्य एजेंडा परियोजनाओं के प्रधान अन्वेषकों एवं सह-प्रधान अन्वेषकों द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक प्रतिवेदनों की समीक्षा करना तथा निर्धारित मानकों के अनुसार अनुदान की प्रथम किस्त जारी करने के संबंध में अनुशंसा करना था। बैठक के दौरान प्रत्येक परियोजना के प्रधान अन्वेषक ने अपनी परियोजना की प्रगति पर संक्षिप्त प्रस्तुति दी। इसके उपरांत विशेषज्ञ समीक्षा समिति के सदस्यों द्वारा सुझाव एवं आवश्यक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए। बैठक का समापन चयनित परियोजनाओं के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार अनुदान की प्रथम किस्त जारी करने की अनुशंसा के साथ हुआ।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष 2026 की प्रथम तिमाही बैठक, 10 जून, 2026, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, दिल्ली

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष 2026 की प्रथम तिमाही बैठक दिनांक 10 जून 2026 को कार्यकारी निदेशक एवं समिति के अध्यक्ष श्री मधुप व्यास (भा.प्र.से.) की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में अध्यक्ष महोदय के अतिरिक्त, तत्कालीन संयुक्त निदेशक, कर्नल मनोरम यादव, एसएम, श्री रणदीप कुमार राणा (वरिष्ठ सलाहकार), सुश्री सुषमा गुलेरिया (सह-प्राध्यापक), सुश्री नाजिया खान (जनसंपर्क अधिकारी), श्रीमती रीतू सूद (प्रशासनिक अधिकारी), श्री हेमंत कुमार (कम्प्यूटर प्रोग्रामर), श्री संतोष कुमार तिवारी (पुस्तकालयाध्यक्ष), श्री रवीन्द्र सिंह (प्रभारी, प्रकाशन प्रकोष्ठ) एवं श्री संजय कुमार (परामर्शदाता, राजभाषा) उपस्थित रहे। बैठक के प्रारंभ में दिनांक 06 मार्च 2026 को आयोजित पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों की समीक्षा की गई तथा लंबित कार्यों के शीघ्र निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। विचार-विमर्श के दौरान समिति ने सर्वसम्मति से संस्थान के संक्षिप्त हिन्दी नाम के रूप में 'रा.आ.प्र.सं.' के स्थान पर 'एनआईडीएम' के प्रयोग को स्वीकृति प्रदान की। संस्थान में देश-विदेश से आने वाले प्रशिक्षणार्थियों एवं आगंतुकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रमुख मार्गों एवं प्रवेश स्थलों पर हिन्दी एवं अंग्रेजी में संस्थान के दिशासूचक साइनबोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया गया तथा इस कार्य को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने हेतु अनुरक्षण अनुभाग को आवश्यक निर्देश दिए गए। समिति ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रारंभ में प्रदर्शित किए जाने वाले संस्थान के परिचयात्मक ऑडियो-विजुअल क्लिप का हिन्दी संस्करण तैयार करने पर भी बल दिया। बैठक में राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अनुपालन के अंतर्गत हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिए जाने के निर्देश सभी प्रभागों को पुन: जारी किए गए। अध्यक्ष महोदय ने संस्थान में राजभाषा संबंधी पद के सृजन पर सहमति व्यक्त करते हुए प्रशासन अनुभाग को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त संस्थान की त्रैमासिक पत्रिका 'टाइडिंग्स' के हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करणों का प्रत्येक तिमाही में समयबद्ध प्रकाशन एवं वितरण सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया। बैठक का समापन अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

राजभाषा हिन्दी के प्रयोग में तकनीकी शब्दावली का अनुप्रयोग विषय पर हिन्दी कार्यशाला का आयोजन, 19 जून 2026, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, दिल्ली

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा दिनांक 19 जून 2026 को दिल्ली परिसर में 'राजभाषा हिन्दी के प्रयोग में तकनीकी शब्दावली का अनुप्रयोग' विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। संस्थान के दैनिक कार्यों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यशाला में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तकनीकी शब्दावली के प्रभावी एवं मानकीकृत प्रयोग संबंधी व्यापक जानकारी प्रदान की गई। कार्यशाला का आयोजन पुस्तकालयाध्यक्ष एवं समन्वयकर्ता श्री संतोष कुमार तिवारी द्वारा संस्थान के कार्यकारी निदेशक श्री मधुप व्यास (भा.प्र.से.) के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम के दौरान संस्थान के संयुक्त निदेशक कर्नल विनीत बाँगा ने मुख्य वक्ता श्री नानक चंद, उप निदेशक (राजभाषा), गृह मंत्रालय को प्लांटर भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही, संस्थान परिवार की ओर से नवनियुक्त संयुक्त निदेशक कर्नल विनीत बाँगा का भी प्लांटर भेंट कर हार्दिक स्वागत किया गया। उद्घाटन सत्र में संस्थान के वरिष्ठ सलाहकार श्री कृष्ण कुमार (भा.प्र.से.), सेवानिवृत, ने तकनीक के माध्यम से दैनिक कार्यालयीन कार्यों में राजभाषा हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डाला। अपने व्याख्यान में मुख्य वक्ता श्री नानक चंद ने कहा कि मानकीकृत तकनीकी शब्दावली का प्रयोग न केवल कार्यालयीन कार्यों को अधिक स्पष्ट, सटीक एवं प्रभावी बनाता है, बल्कि राजभाषा हिन्दी के प्रगतिशील उपयोग को भी सुदृढ़ करता है। कार्यशाला का समापन परामर्शदाता (राजभाषा) श्री संजय कुमार द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) की आपदा प्रबंधन योजना के मसौदे पर विशेषज्ञ समूह की बैठक, 19 जून 2026, दिल्ली

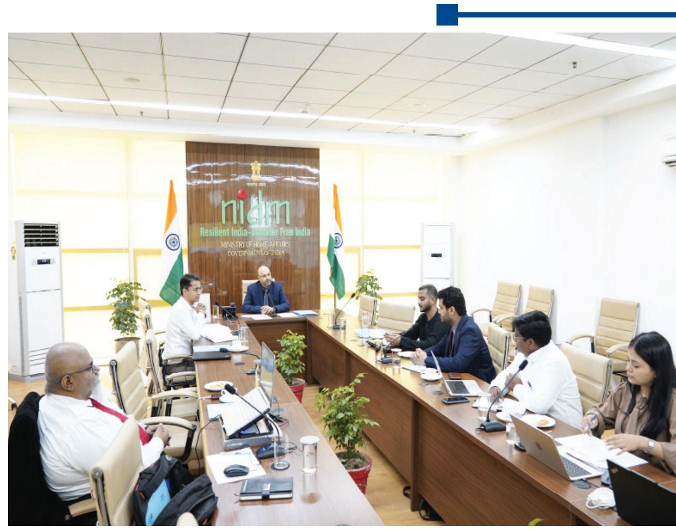

पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) की प्रारूप आपदा प्रबंधन योजना तथा आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल की समीक्षा के उद्देश्य से 19 जून 2026 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, दिल्ली में एक विशेषज्ञ समूह बैठक आयोजित की गई।

बैठक की अध्यक्षता कर्नल विनीत बाँगा, संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने की। इस अवसर पर डॉ. रविन्द्र सिंह (प्रमुख अन्वेषक) तथा एनआईडीएम की टीम के साथ विशेषज्ञ समूह के सदस्य डॉ. सप्तर्षि बसु, प्राचार्य, ओईआरसी अकादमी; श्री श्रीकांत बथुला, वैज्ञानिक अधिकारी (एफ), भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र; श्री आलोक कुमार, मुख्य प्रबंधक (अग्निशमन सेवाएँ), एटीआई-ओएनजीसी; श्री तारिक अहमद, अनुसंधान सहयोगी, नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन; तथा श्री सुरेन्द्र मिडाटाडा, अनुसंधान सहयोगी, राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, ग्रीन पोर्ट्स एवं पोत परिवहन (NCoEGPS), टेरी, ने सक्रिय रूप से विचार-विमर्श में भाग लिया।

विचार-विमर्श के दौरान विशेषज्ञ समूह को संयुक्त निदेशक द्वारा परियोजना की प्रगति तथा अब तक प्राप्त प्रमुख उपलब्धियों से विस्तारपूर्वक अवगत कराया गया। विशेषज्ञ समूह के सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों एवं तकनीकी परामर्श ने प्रशिक्षण मॉड्यूल के प्रारूप तथा पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय की प्रारूप आपदा प्रबंधन योजना को अंतिम रूप देने की दिशा में स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान किया।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की भूमिका पर कार्यशाला, 30 जून 2026, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश

कार्यशाला में आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अंतरिक्ष आधारित प्रौद्योगिकियों, सुदूर संवेदन, भौगोलिक सूचना प्रणाली तथा भू-स्थानिक अनुप्रयोगों की बढ़ती भूमिका पर विशेष प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में आपदा निगरानी, जोखिम आकलन, पूर्व चेतावनी, आपातकालीन प्रतिक्रिया तथा पुनर्प्राप्ति योजना के लिए उन्नत तकनीकी उपकरणों एवं डिजिटल प्लेटफॉर्मों के उपयोग का प्रदर्शन किया गया। विचार-विमर्श के दौरान साक्ष्य-आधारित निर्णय-निर्माण के लिए भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों के प्रभावी उपयोग तथा आपदा प्रबंधन प्रक्रियाओं में राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन डेटाबेस के उपयोगिता पर विशेष बल दिया गया। कार्यशाला ने ज्ञान के आदान-प्रदान, विभिन्न एजेंसियों के मध्य सहयोग तथा क्षमता निर्माण को भी प्रोत्साहित किया, ताकि आपदा जोखिम न्यूनीकरण की योजना-निर्माण प्रक्रिया एवं प्रत्यास्थता निर्माण संबंधी पहलों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रभावी एवं व्यापक एकीकरण सुनिश्चित किया जा सके।

एनआईडीएम डिजिटल लर्निंग पहल

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, माननीय प्रधानमंत्री के आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु 10-सूत्रीय एजेंडा, विशेष रूप से बिंदु सख्या 6, जिसमें आपदा जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग पर बल दिया गया है, के अनुरूप अपने गतिशील एवं प्रभावशाली डिजिटल प्रशिक्षण तंत्र के माध्यम से क्षमता निर्माण के क्षेत्र में निरंतर नए मानदंड स्थापित कर रहा है। iGOT कर्मयोगी तथा अपने समर्पित ई-लर्निंग पोर्टल जैसे डिजिटल मंचों का प्रभावी उपयोग करते हुए, एनआईडीएम दक्षता-आधारित, व्यावहारिक तथा नीतिगत दृष्टि से प्रासंगिक शिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से आपदा प्रत्यास्थता को सुशासन की मुख्यधारा में प्रभावी रूप से समाहित कर रहा है। iGOT कर्मयोगी मंच के अंतर्गत एनआईडीएम द्वारा नौ विविध ऑनलाइन पाठ्यक्रम अंग्रेज़ी, हिंदी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, बांग्ला, मलयालम तथा ओड़िया सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये पाठ्यक्रम समावेशिता सुनिश्चित करने के साथ-साथ देशव्यापी पहुँच को भी सुदृढ़ करते हैं। अपनी बढ़ती प्रभावशीलता को दर्शाते हुए इस पहल के अंतर्गत अब तक 274990+ से अधिक नामांकन, 184860+ से अधिक सफल पाठ्यक्रम पूर्णताएँ तथा 5 में से 4.5 की प्रभावशाली औसत शिक्षार्थी रेटिंग प्राप्त हुई है, जो पाठ्यवस्तु की गुणवत्ता, प्रासंगिकता एवं प्रभावी प्रस्तुति का प्रमाण है। इसके पूरक के रूप में, एनआईडीएम के ई-लर्निंग कार्यक्रमों के अंतर्गत एक बुनियादी तथा नौ विषयगत प्रमुख पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। साथ ही, वार्षिक क्षमता निर्माण योजना के अंतर्गत संस्थान अपने ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का निरंतर विस्तार कर रहा है, जिससे विभिन्न हितधारकों की उभरती प्रशिक्षण आवश्यकताओं को प्रभावी रूप से पूरा किया जा सके। एनआईडीएम की 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण संवाद व्याख्यान श्रृंखला' आपदा जोखिम न्यूनीकरण के उभरते विषयों पर ज्ञान-विस्तार हेतु एक सशक्त मंच के रूप में कार्य करती है। इस श्रृंखला के माध्यम से विशेषज्ञों, पेशेवरों तथा नीति-निर्माताओं को एक साथ लाकर अनुसंधान, नीति संवाद तथा व्यावहारिक शिक्षण का समन्वय किया जाता है। इस व्याख्यान श्रृंखला में समकालीन एवं महत्वपूर्ण विषयों पर उच्चस्तरीय विचार-विमर्श आयोजित किए जाते हैं, जिनके रिकॉर्ड किए गए सत्रों को दीर्घकालिक क्षमता निर्माण के लिए डिजिटल शिक्षण संसाधनों के रूप में संकलित एवं उपलब्ध कराया जाता है। हाल के सत्रों में इन विषयों पर विशेष रूप से चर्चा की गई है।

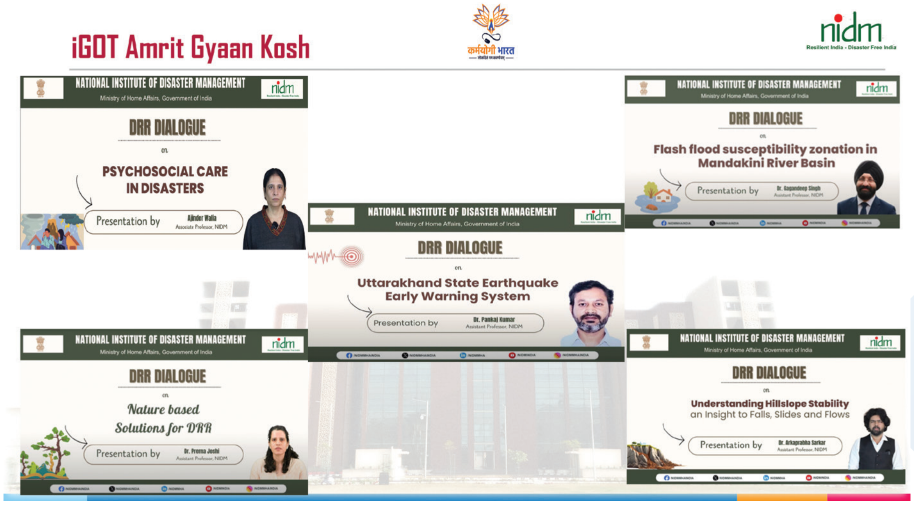

अमृत ज्ञान कोष के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की आपदा जोखिम न्यूनीकरण संवाद व्याख्यान श्रृंखला विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, पेशेवरों तथा विभिन्न संस्थानों के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान एवं सहयोग के लिए एक सशक्त मंच के रूप में कार्य करती है। यह श्रृंखला आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित उभरते विषयों पर सार्थक विमर्श को प्रोत्साहित करते हुए ज्ञान-विनिमय, नीति-चर्चा तथा सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

इस संवाद श्रृंखला के अंतर्गत अब तक आपदा जोखिम वित्तपोषण, प्रकृति-आधारित समाधान, मंदाकिनी बेसिन में आकस्मिक बाढ़ की संवेदनशीलता, तथा उत्तराखंड में भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श आयोजित किए जा चुके हैं।

इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हाल के सत्रों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका, मनोसामाजिक सहायता, इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम, आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु प्रकृति-आधारित समाधान, प्रकृति-आधारित समाधानों के लिए IUCN वैश्विक मानक, पर्वतीय ढालों की स्थिरता की समझ, तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण में मनोसामाजिक देखभाल जैसे समसामयिक विषयों को शामिल किया गया है। इन पहलों के माध्यम से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान देश में आपदा प्रत्यास्थता के क्षेत्र में राष्ट्रीय ज्ञान केंद्र के रूप में अपनी भूमिका को निरंतर सुदृढ़ कर रहा है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का स्व-अध्ययन कार्यक्रम एक वेब-आधारित शिक्षण मंच है, जिसे आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में सतत् क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। यह कार्यक्रम विद्यार्थियों, सरकारी अधिकारियों, आपदा प्रबंधन के व्यावसायिकों, स्वयंसेवकों, शोधकर्ताओं तथा आम नागरिकों के लिए तैयार किया गया है और उन्हें किसी भी समय तथा किसी भी स्थान से गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री तक नि:शुल्क एवं सुलभ पहुँच प्रदान करता है। एसएसपी शिक्षार्थियों को अपनी सुविधा एवं गति के अनुसार स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे वे आपदा प्रबंधन के मूलभूत सिद्धांतों के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित विशिष्ट ज्ञान भी अर्जित कर सकते हैं। वर्तमान में इस मंच पर दस व्यापक अध्ययन मॉड्यूल उपलब्ध हैं, जिनमें आपदा प्रबंधन की मूलभूत अवधारणाएँ, समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन, नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों हेतु मार्गदर्शिका, बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन का परिचय, चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन का परिचय, आपदा स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन का अवलोकन, व्यापक भूस्खलन जोखिम प्रबंधन, विद्यालय सुरक्षा, भूकम्प जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन का परिचय तथा औद्योगिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन का परिचय जैसे प्रमुख विषय शामिल हैं।

विशेषज्ञों द्वारा विकसित ज्ञान-सामग्री को स्व-अध्ययन आधारित प्रारूप में उपलब्ध कराकर एसएसपी आपदा पूर्व तैयारी को सुदृढ़ बनाने, समुदायों की प्रत्यास्थता को सशक्त करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में जोखिम के प्रति सजगता पूर्वक निर्णय लेने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

अन्य संस्थागत क्रियाकलाप

आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रत्यास्थता शिक्षा पर यूएनडीआरआर-गेटी कार्यशाला में एनआईडीएम की सहभागिता

आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु प्रशिक्षण संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन यूएनडीआरआर ग्लोबल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (UNDRR-GETI) द्वारा इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (IASIA) के सहयोग से 16 से 19 जून, 2026 तक इंचियोन, कोरिया गणराज्य में आयोजित किया गया। इस कार्यशाला में विश्वभर के विश्वविद्यालयों, प्रशिक्षण संस्थानों तथा आपदा प्रबंधन संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु जोखिम न्यूनीकरण के प्रभावी एकीकरण को सुदृढ़ करना था। कार्यशाला के दौरान यूएनडीआरआर-आईएएसआईए टूलकिट, प्रत्यास्थता आकलन उपकरणों, सुशासन रूपरेखाओं, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों तथा क्षमता विकास के नवाचारी दृष्टिकोणों पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया। इन चर्चाओं के माध्यम से प्रतिभागियों ने प्रतिरोधक क्षमता संपन्न नेतृत्वकर्ताओं एवं व्यवहारिक विशेषज्ञों की नई पीढ़ी तैयार करने के लिए विभिन्न रणनीतियों पर विचार किया।

भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री मधुप व्यास (भा.प्र.से.), कार्यकारी निदेशक ने 'यूएनडीआरआर-आईएएसआईए टूलकिट पर विचार' विषयक सत्र में पैनल सदस्य के रूप में सहभागिता की। उन्होंने शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण पारितंत्रों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को मुख्यधारा से

जोड़ने तथा प्रत्यास्थता सुदृढ़ीकरण के लिए संस्थागत क्षमताओं को सशक्त बनाने संबंधी अपने विचार एवं अनुभव साझा किए।

उत्कृष्टता का नया प्रतिमान : एनआईडीएम को 4-स्टार 'अति उत्कृष्ट' श्रेणी के साथ पुनः मान्यता प्राप्त

Certificate No.
APP/23/N00242-2

CAPACITY BUILDING COMMISSION

Certificate of Accreditation

The training Institute **National Institute of Disaster Management** is accredited as **अति उत्कृष्ट/Excellent** under the Capacity Building Commission's National Standards.

The Accreditation shall remain in force subject to continued compliance with the National Standards.The Accreditation needs to be renewed before the expiry date by the training institution following the due process of assessment.

The Accreditation granted on **28/04/2026** is valid until **27/04/2028**

★★★★

Secretary — Capacity Building Commission

Chairperson — Capacity Building Commission

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने 28 अप्रैल, 2026 को भारत सरकार के क्षमता निर्माण आयोग द्वारा राष्ट्रीय मानकों के अंतर्गत पुनः प्रत्यायन प्राप्त करते हुए 4-स्टार (अति उत्कृष्ट) रेटिंग अर्जित कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। श्री मधुप व्यास (भा.प्र.से.), कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम के नेतृत्व में प्राप्त यह प्रतिष्ठित मान्यता आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा नीतिगत-समर्थन के प्रति संस्थान की निरंतर उत्कृष्ट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह उपलब्धि आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रत्यास्थता निर्माण के क्षेत्र में एनआईडीएम की अग्रणी संस्थान के रूप में प्रतिष्ठा को और सुदृढ़ करती है। साथ ही, यह सुशासन, गुणवत्तापूर्ण अधिगम, नवाचार तथा संस्थागत कार्य-निष्पादन के उच्च मानकों को बनाए रखने के प्रति संस्थान की दृढ़ प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करती है।

विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के अवसर पर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा प्रारंभ किए गए राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान में एनआईडीएम की सहभागिता

विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के अवसर पर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा प्रारंभ किए गए राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान के समर्थन में गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा 5 जून, 2026 को नई दिल्ली तथा दक्षिण परिसर (विजयवाड़ा) में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्री मधुप व्यास (भा.प्र.से.), कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम के मार्गदर्शन में संयुक्त निदेशकों, वरिष्ठ अधिकारियों, संकाय सदस्यों तथा कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक इस अभियान में सहभागिता की तथा पर्यावरण संरक्षण, जलवायु प्रत्यास्थता और सतत् विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः अभिव्यक्त किया। यह वृक्षारोपण अभियान इस विश्वास को प्रतिबिंबित करता है कि हरित पर्यावरण सुरक्षित एवं आपदा-प्रत्यास्थ समुदायों के निर्माण की आधारशिला है। देशी प्रजातियों के पौधों का रोपण तथा प्रकृति-आधारित समाधानों को प्रोत्साहित करते हुए संस्थान पारिस्थितिक संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन तथा जलवायु कार्रवाई में निरंतर योगदान दे रहा है। एनआईडीएम पर्यावरणीय निरंतरता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है तथा हरित, सुरक्षित और अधिक आपदा-प्रत्यास्थ भविष्य के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप वृक्षारोपण एवं हरियाली संबंधी पहलों को आगे भी निरंतर प्रोत्साहित करता रहेगा।

श्रीलंका के सिविल सेवा अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल का एनआईडीएम दौरा

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने 3 जून, 2026 को राष्ट्रीय सुशासन केंद्र द्वारा आयोजित एक अध्ययन भ्रमण के अंतर्गत श्रीलंका के 40 सिविल सेवकों के एक विशिष्ट प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आपदा जोखिम प्रबंधन, सुशासन, संस्थागत क्षमता निर्माण तथा आपदा प्रत्यास्थता को सुदृढ़ बनाने में एनआईडीएम की भूमिका से प्रतिनिधिमंडल को अवगत कराना था।

भ्रमण के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने श्री मधुप व्यास (भा.प्र.से.), कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम सहित संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों एवं संकाय सदस्यों के साथ संवाद किया। प्रो. नवनीत कुमार ने भारत की आपदा जोखिम रूपरेखा, संस्थागत व्यवस्था तथा प्रशिक्षण, अनुसंधान, नीति-समर्थन एवं उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग के क्षेत्र में एनआईडीएम के योगदान पर विस्तृत प्रस्तुति दी। वहीं, डॉ. गगनदीप सिंह, सहायक प्रोफेसर, एनआईडीएम ने भारत की आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं शमन संबंधी पहलों पर प्रकाश डालते हुए भारत एवं श्रीलंका के आपदा जोखिम प्रोफ़ाइल का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया। यह संवाद ज्ञान के आदान-प्रदान, पारस्परिक सीख तथा आपदा शासन के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य-पद्धतियों को साझा करने का एक महत्वपूर्ण मंच सिद्ध हुआ। साथ ही, इसने भारत-श्रीलंका के बीच आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रत्यास्थता निर्माण के क्षेत्र में सहयोग को और अधिक सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

बिहार के माननीय राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कार्यकारी निदेशक, श्री मधुप व्यास, (भा.प्र.से.) के नेतृत्व में संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने बिहार के माननीय राज्यपाल, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत) से शिष्टाचार भेंट की। इस भेंट ने अंतरराष्ट्रीय क्षमता निर्माण, डिजिटल अधिगम तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में एनआईडीएम की वर्तमान पहलों पर सार्थक विचार-विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। बैठक के दौरान माननीय राज्यपाल ने संस्थागत सहयोग को और अधिक सुदृढ़ करने, सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार के माध्यम से आपदा संबंधी जन-जागरूकता बढ़ाने, व्यापक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल मंचों के प्रभावी उपयोग तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में क्षेत्रीय व्यावहारिक अनुभवों के समावेशन की आवश्यकता पर बल दिया। विचार-विमर्श के दौरान आपदा पूर्व तैयारी को राष्ट्रीय प्रत्यास्थता के साथ समन्वित करने तथा अंतिम छोर तक प्रभावी पहुँच और समुदाय आधारित आपदा पूर्व तैयारी को सुदृढ़ करने वाली साझेदारियों को बढ़ावा देने के महत्व पर भी विशेष रूप से प्रकाश डाला गया। इस संवाद ने नवाचार, सहयोग तथा ज्ञान के आदान-प्रदान के माध्यम से एक प्रत्यास्थ, सुदृढ़ रूप से तैयार एवं जोखिम-सूचित समाज के निर्माण के प्रति साझा प्रतिबद्धता को पुनः पुष्ट किया।

विषयगत दृष्टिकोण

संस्थागत रूपांतरण की यात्रा : एनआईडीएम की प्रत्यायन गाथा

श्री कृष्ण कुमार, भा.प्र.से. (सेवानिवृत)
वरिष्ठ सलाहकार, एनआईडीएम

लोक सेवा में कई दशकों के अपने अनुभव ने मुझे यह सिखाया है कि किसी संस्था की वास्तविक पहचान केवल उसके दायित्वों से नहीं होती, बल्कि उससे होती है कि वह प्रतिदिन, बिना किसी आडंबर के, कितनी निष्ठा, अनुशासन और निरंतरता के साथ उत्कृष्टता की दिशा में अग्रसर रहती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की हालिया प्रत्यायन यात्रा, जो 28 अप्रैल, 2026 को क्षमता निर्माण आयोग द्वारा प्रदान की गई 4-स्टार (अति उत्कृष्ट) रेटिंग के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि पर पहुँची, ऐसी ही प्रेरक यात्रा है, जिसका मैं स्वयं साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सका।

जब वर्ष 2024 में एनआईडीएम को 2-स्टार रेटिंग प्राप्त हुई थी, तब उस संख्या को केवल एक प्रशासनिक औपचारिकता मानकर नज़र अंदाज़ किया जा सकता था। किंतु सुशासन के क्षेत्र में सख्याएँ मात्र सख्याएँ नहीं होतीं; वे संस्था का दर्पण होती हैं। उस दर्पण ने हमें आत्ममंथन, पुनर्संगठन तथा उत्कृष्टता की दिशा में आगे बढ़ने का एक ईमानदार अवसर प्रदान किया।

क्षमता निर्माण आयोग का प्रत्यायन ढाँचा केवल दस्तावेज़ी औपचारिकताओं की अपेक्षा नहीं करता, बल्कि यह अपेक्षा करता है कि संस्था जो होने का दावा करती है, वह वास्तव में अपने कार्यों और उपलब्धियों से उसे प्रमाणित भी करे। एक से पाँच के पैमाने पर आधारित साक्ष्य-आधारित एवं संरचित मूल्यांकन अपनी अवधारणा और क्रियान्वयन, दोनों ही दृष्टियों से अत्यंत कठोर है, क्योंकि संस्थागत विश्वसनीयता किसी समझौते का परिणाम नहीं होती; उसे अर्जित करना पड़ता है।

तीन माह तक चले स्व-मूल्यांकन, दस्तावेज़ों के सत्यापन तथा स्थल पर विस्तृत मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान एनआईडीएम ने इस कठोरता को अनिच्छा से नहीं, बल्कि पूर्ण विश्वास और प्रतिबद्धता के साथ स्वीकार किया।

इस प्रत्यायन चक्र की सबसे बड़ी विशेषता उत्तरदायित्व की भावना में आया मौलिक परिवर्तन था। संस्थागत दायित्व कुछ व्यक्तियों तक सीमित रहने के बजाय आठ समर्पित कार्य-दलों में विभाजित किया गया। प्रत्येक दल की स्पष्ट जिम्मेदारियाँ निर्धारित थीं, प्रत्येक अपने कार्य के प्रति उत्तरदायी था और सभी एक साझा उद्देश्य से जुड़े हुए थे। मेरे अनुभव में यही वह अंतर है, जो किसी संस्था को केवल बेहतर प्रदर्शन करने वाली संस्था से आगे बढ़ाकर वास्तविक रूपांतरण की दिशा में ले जाता है। कार्यकारी निदेशक के दूरदर्शी नेतृत्व तथा वरिष्ठ सलाहकार (प्रशिक्षण प्रभाग) के रणनीतिक मार्गदर्शन में साझा उत्तरदायित्व की ऐसी भावना विकसित हुई, जिसने प्रशासनिक ढाँचों में विरले दिखाई देने वाली सामूहिक कार्य-संस्कृति को साकार रूप दिया।

दो दिवसीय स्थल-आधारित मूल्यांकन केवल निरीक्षण नहीं था; वह एक संस्थागत संवाद था। मूल्यांकनकर्ताओं ने केवल यह नहीं देखा कि दस्तावेज़ों में क्या लिखा है, बल्कि यह भी परखा कि संस्था ने उन सिद्धांतों को किस सीमा तक समझा, आत्मसात किया और व्यवहार में उतारा है। तैयारी आवश्यक थी, किंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण थी कार्यों की प्रामाणिकता।

मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि एक लोक सेवक को अपने कार्य में वास्तविक संतोष कब प्राप्त होता है। मेरा उत्तर सदैव एक ही रहता है—जब सामूहिक प्रयास मापनीय और सार्थक परिणामों में परिवर्तित होते हैं। यह संतोष व्यक्तिगत उपलब्धियों से नहीं, बल्कि उस शांत गर्व से उत्पन्न होता है, जब पूरी टीम चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में एकजुट रहकर उत्कृष्ट परिणाम प्रस्तुत करती है।

इस प्रत्यायन यात्रा ने मुझे एक सुव्यवस्थित फुटबॉल टीम की याद दिलाई, जिसकी पहचान किसी एक स्टार खिलाड़ी से नहीं, बल्कि प्रत्येक खिलाड़ी की स्पष्ट भूमिका, अनुशासित प्रदर्शन और साझा उद्देश्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से होती है। प्रत्येक इकाई ने अपना योगदान दिया, प्रत्येक स्तर पर आवश्यक सुधार किए गए और पूरी टीम एक साथ आगे बढ़ती रही।

देश के चुनिंदा 4-स्टार प्रत्यायित संस्थानों की श्रेणी में स्थान प्राप्त करना निस्संदेह गर्व और संतोष का विषय है। किंतु इस उपलब्धि की सबसे स्थायी विरासत वह कार्य-संस्कृति है, जिसने टीम भावना, उत्तरदायित्व, पारस्परिक विश्वास और संस्थागत आत्मविश्वास को और अधिक सुदृढ़ किया है।

इस उपलब्धि में योगदान देने वाले एनआईडीएम परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए मेरा एक ही संदेश है—उत्कृष्टता कभी संयोगवश प्राप्त नहीं होती; यह एक सचेत विकल्प होती है। आपने उस विकल्प को अपनाया है और यह आपकी उपलब्धियों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। अब पाँच-स्टार रेटिंग की यात्रा आरंभ होती है, एक लक्ष्य के रूप में नहीं, बल्कि उस स्वाभाविक परिणाम के रूप में, जिसकी ओर हमारा संस्थान निरंतर विकसित हो रहा है।

भारत में हीटवेव कॉरिडोर : अत्यधिक तापमान एवं हॉटस्पॉट क्षेत्रों का स्थानिक वितरण

डॉ. जी. सीएच. सत्यनारायण
एसोसिएट प्रोफेसर, एनआईडीएम

औसत अधिकतम तापमान तथा 42° सेल्सियस से अधिक तापमान वाले दिनों की संख्या के आधार पर, उत्तर-पश्चिम भारत से दक्षिण-मध्य भारत तक एक प्रमुख हीटवेव कॉरिडोर (या ''हीट रिवर'') का पता चलता है। यह कॉरिडोर राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ और उनसे सटे मध्य भारतीय इलाकों से होकर गुज़रता है (चित्र 1) सर्वाधिक औसत अधिकतम तापमान (45° सेल्सियस से अधिक) और सबसे ज़्यादा भीषण गर्मी वाले दिन उत्तर-पश्चिमी एवं मध्य भारत में देखे जाते हैं, जो भारतीय उपमहाद्वीप में लगातार बने रहने वाले 'हीट हॉटस्पॉट' की मौजूदगी को दिखाते हैं। यह पैटर्न उन पिछली स्टडीज़ से मेल खाता है जिनमें विदर्भ क्षेत्र में एक खास ''हॉट ब्लॉब'' की पहचान की गई थी; यहाँ तापमान और लू (हीटवेव) की बारंबारता अक्सर राजस्थान के थार रेगिस्तान वाले इलाके की तुलना में ज़्यादा होती है।

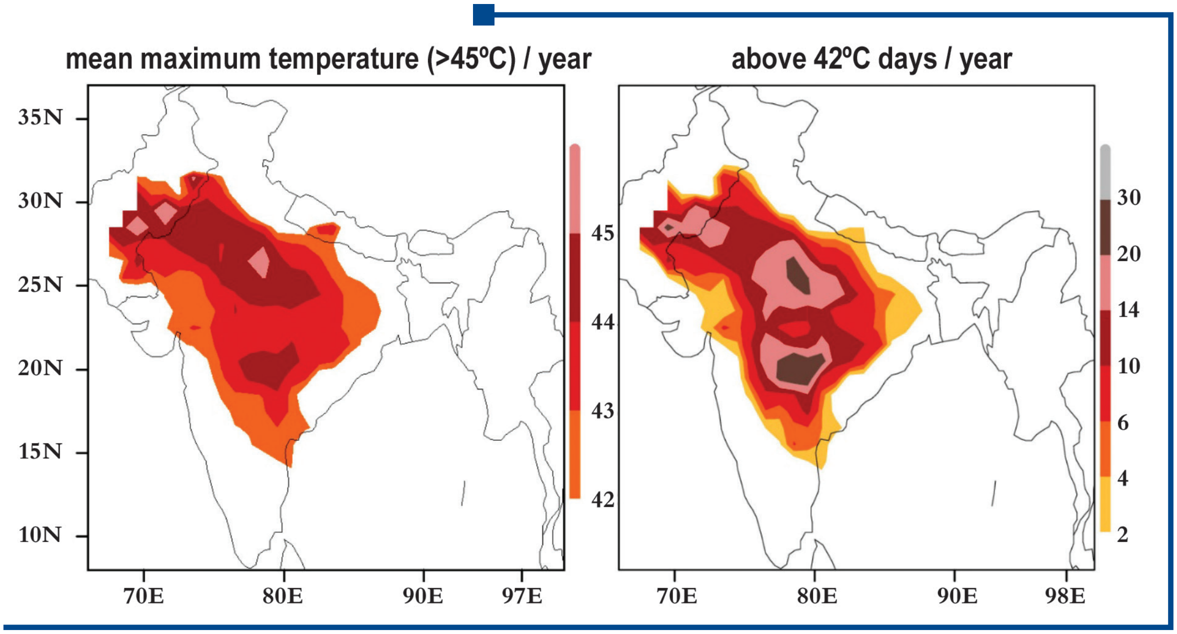

चित्र-1. वर्ष 1951-2025 की अवधि के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग के ग्रिडेड तापमान आँकड़ों के आधार पर भारत में औसत अधिकतम तापमान तथा 42° सेल्सियस से अधिक अधिकतम तापमान वाले दिनों की वार्षिक आवृत्ति का स्थानिक वितरण। इसमें उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में हीटवेव (लू) के मुख्य कॉरिडोर और गर्मी के प्रमुख हॉटस्पॉट को दिखाया गया है।

इस हीटवेव कॉरिडोर का विकास भूमि-वायुमंडलीय तंत्र की अनेक परस्पर संबद्ध प्रक्रियाओं का परिणाम है। इनमें प्रतिचक्रवाती परिसंचरण की स्थिरता, वायुमंडलीय अवतलन, बादलों की कम उपस्थिति, सौर विकिरण में वृद्धि, मृदा आर्द्रता में कमी तथा संवेदनशील तापमान प्रवाह में वृद्धि जैसी प्रक्रियाएं सतही तापमान में अत्यधिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं। अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के उपोष्णकटिबंधीय उच्च-दाब तंत्रों के मध्य स्थित कोल (COL) क्षेत्र मध्य भारत, विशेषकर विदर्भ क्षेत्र, में तापमान के संचयन को बढ़ावा देता है, जिसके परिणामस्वरूप लंबे समय तक उच्च तापमान बना रहता है तथा हीटवेव की घटनाओं में वृद्धि होती है। बड़े पैमाने पर जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक भी अहम भूमिका निभाते हैं। मज़बूत अल-नीनो (El Niño) घटनाओं के कमज़ोर पड़ने के दौरान, पश्चिमी उत्तरी प्रशांत महासागर से बंगाल की खाड़ी तक फैली असामान्य प्रतिचक्रवाती हवाओं की गति संवहन को रोकती है, हवा में नमी कम करती है और सतह पर शॉर्टवेव रेडिएशन को बढ़ाती है। इससे मध्य और उत्तर-पश्चिम भारत में हीटवेव की स्थिति और गंभीर हो जाती है।

पूर्ववर्ती विश्लेषणों से यह भी स्पष्ट हुआ है कि हीटवेव की शुरुआत प्राय: राजस्थान, उत्तर-मध्य भारत तथा पूर्वी महाराष्ट्र (विदर्भ) के उच्चतम तापमान वाले क्षेत्रों से होती है। इसके बाद निम्न-स्तरीय पवनों (Low-level Wind Advection) के असामान्य प्रवाह के माध्यम से ये हीटवेव पूर्वी एवं दक्षिण-पूर्वी भारत की ओर अग्रसर होती हैं।

42° सेल्सियस से अधिक तापमान वाले दिनों की बढ़ती आवृत्ति तथा हीटेवेव की दीर्घावधि घटनाएँ इस बात का संकेत देती हैं कि हाल के दशकों में वैश्विक तापमान के प्रभाव से यह हीटवेव कॉरिडोर और अधिक सशक्त एवं स्पष्ट होता जा रहा है। यह स्थिति मानव स्वास्थ्य, कृषि, जल संसाधनों, ऊर्जा की मांग तथा आपदा प्रबंधन के लिए गंभीर चुनौतियाँ उत्पन्न कर रही है।

दक्षिण-पूर्वी भारत, विशेषकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा, में हाल के दशकों में हीटवेव की तीव्रता उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक सामाजिक-आर्थिक प्रभाव तथा जनहानि देखी गई है। अत: यह पहचाना गया हीटवेव कॉरिडोर जलवायु संवेदनशीलता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है तथा यह भारत में अधिक प्रभावी ताप-पूर्व चेतावनी प्रणालियों (Heat Early Warning Systems), ताप-स्वास्थ्य कार्ययोजनाओं, जलवायु अनुकूलन उपायों तथा जोखिम के प्रति सतर्कता पूर्वक आपदा प्रबंधन रणनीतियों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।

चरम मौसमीय घटनाओं से उत्पन्न कृषि हानि एवं खाद्य सुरक्षा का उभरता जोखिम परिदृश्य: पंजाब बाढ़ के संदर्भ में

डॉ. कुंदन देवल
परामर्शदाता, एनआईडीएम

मानसून-2026 के आगमन के साथ ही सामुदायिक आजीविका की सुरक्षा तथा संभावित अनिश्चितताओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए तैयारियाँ प्रारम्भ हो गई हैं। आपदा प्रबंधकों, कृषि योजनाकारों तथा नीति-निर्माताओं के लिए समयबद्ध तैयारी और दीर्घकालिक शमन उपाय अत्यंत आवश्यक हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मौसमी पूर्वानुमान के अनुसार देश में वर्षा दीर्घावधि औसत (Long Period Average—LPA) का लगभग 90 प्रतिशत रहने की संभावना व्यक्त की गई है, जो सामान्य से कम वर्षा का संकेत देती है। तथापि, पूर्व के अनुभव दर्शाते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर कुल वर्षा के आँकड़े अक्सर स्थानीय स्तर पर वर्षा के व्यापक भौगोलिक एवं समयगत अंतर को प्रतिबिंबित नहीं करते। सामान्य मानसून वाले वर्षों में भी अल्प अवधि में अत्यधिक तीव्र वर्षा की घटनाएँ आकस्मिक बाढ़, नदीय बाढ़ तथा शहरी जलभराव जैसी आपदाओं का कारण बन सकती हैं, जबकि उसी समय अन्य क्षेत्रों में वर्षा की कमी के कारण सूखे जैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। बदलती जलवायु के परिप्रेक्ष्य में अत्यधिक जल की स्थिति और जल की कमी—इन दोनों चुनौतियों का एक साथ प्रभावी प्रबंधन आपदा जोखिम प्रबंधन की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में से एक बन गया है।

राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन (NASA) द्वारा ग्रैविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट (GRACE) तथा ग्रैविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट फॉलो-ऑन (GRACE-FOLLOW-ON) उपग्रह मिशनों से प्राप्त प्रेक्षणों पर आधारित आकलनों से संकेत मिलता है कि पिछले एक दशक के दौरान अत्यधिक आर्द्र तथा अत्यधिक शुष्क घटनाओं की आवृत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इन अध्ययनों के अनुसार बढ़ते वैश्विक तापमान बाढ़ और सूखे, दोनों की तीव्रता को बढ़ा रहे हैं। अध्ययन यह भी इंगित करते हैं कि उच्च तापमान के कारण शुष्क अवधियों में वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, जबकि दूसरी ओर वायुमंडल में अधिक नमी धारण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। परिणामस्वरूप, वर्षा की घटनाएँ अधिक तीव्र होती हैं, जिससे अत्यधिक वर्षा एवं बाढ़ की घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है।

वैज्ञानिक आकलनों से स्पष्ट होता है कि अत्यधिक आर्द्र तथा अत्यधिक शुष्क मौसमीय घटनाएँ निरंतर अधिक बार और अधिक तीव्रता के साथ घटित हो रही हैं, जिससे कृषि, आजीविका, जल संसाधनों तथा खाद्य प्रणालियों के समक्ष नई चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं। भारत जैसे देश, जहाँ लाखों लोगों की आजीविका प्रत्यक्ष रूप से कृषि जैसे जलवायु-संवेदनशील क्षेत्रों पर निर्भर है, वहाँ इन परिवर्तनों के दूरगामी प्रभाव अत्यंत गंभीर हैं। कृषि क्षेत्र आज भी व्यापक रूप से जलवायु परिस्थितियों पर निर्भर है, और चरम मौसमीय घटनाएँ फसल उत्पादन, पशुधन प्रणाली, ग्रामीण आजीविका, खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं तथा बाजार की स्थिरता को निरंतर प्रभावित कर रही हैं। परिणामस्वरूप, खाद्य सुरक्षा पर भी इनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

चित्र-1 में चरम मौसमीय घटनाओं से उत्पन्न जोखिमों के कारण खाद्य सुरक्षा के चार प्रमुख आयामों—खाद्य उपलब्धता, खाद्य अभिगम्यता, खाद्य उपयोगिता तथा खाद्य स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का निरूपण किया गया है।

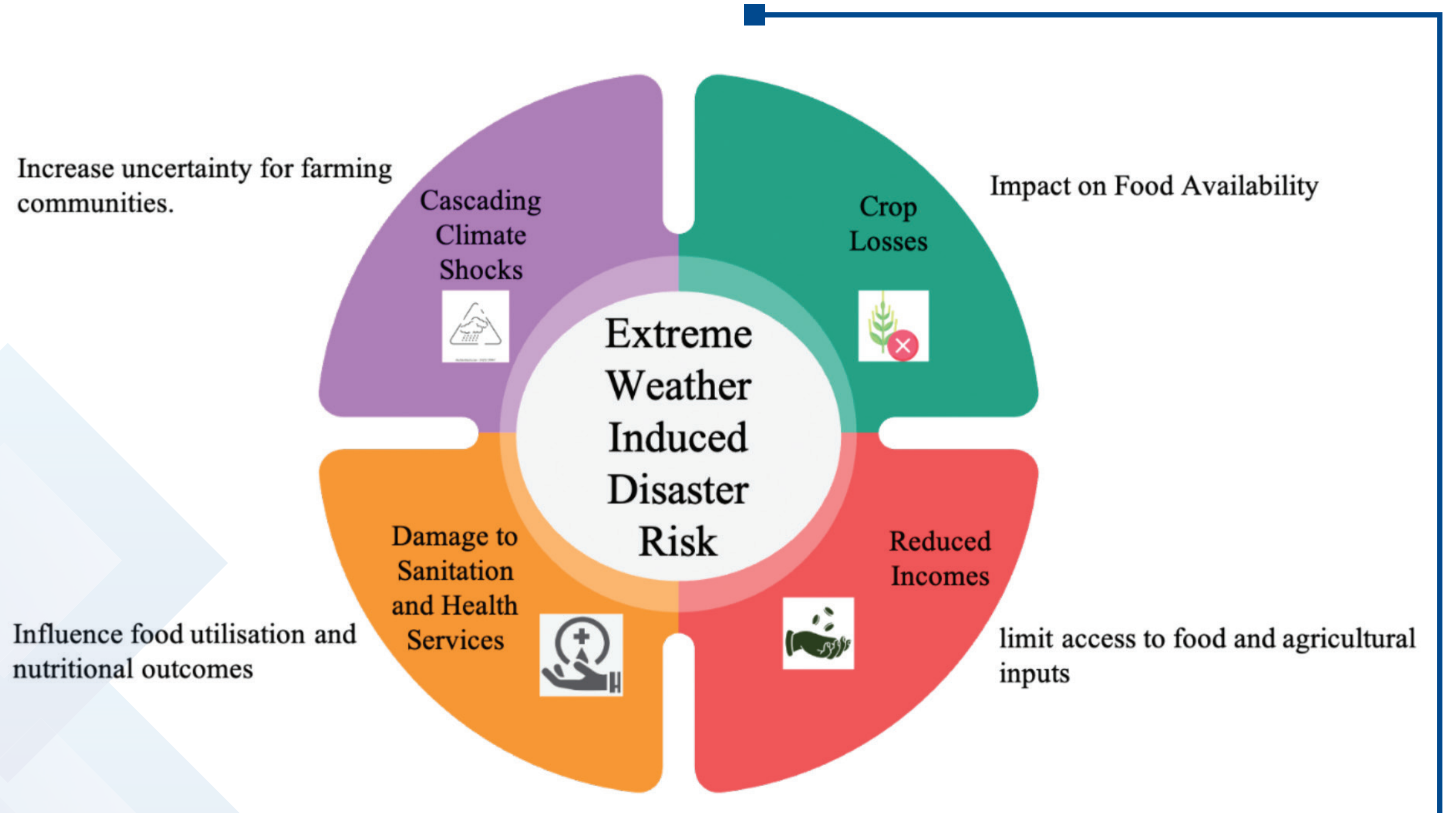

चित्र 1: खराब मौसम और आपदा के जोखिम से जुड़ी खाद्य सुरक्षा के विभिन्न पहलू

फसलों की क्षति का प्रत्यक्ष प्रभाव खाद्य उपलब्धता पर पड़ता है, जबकि कम आमदनी की वजह से पदार्थों तथा कृषि के लिए मिलने वाली ज़रूरी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। जलापूर्ति, स्वच्छता तथा स्वास्थ्य सेवाओं को होने वाली क्षति खाद्य उपयोगिता एवं पोषण संबंधी परिणामों को प्रभावित कर सकती है। बार-बार आने वाले जलवायु संकट खाद्य उत्पादन प्रणालियों की स्थिरता को कमज़ोर करते हैं और खेती कृषक समुदायों के लिए अनिश्चितता बढ़ाते हैं। इस प्रकार, आपदा जोखिम और खाद्य सुरक्षा परस्पर गहराई से जुड़े हुए विषय बनते जा रहे हैं, जिनके समाधान के लिए समन्वित एवं बहु-क्षेत्रीय नीतिगत दृष्टिकोण की आवश्यकता है। परिणामस्वरूप, खाद्य सुरक्षा अब केवल कृषि क्षेत्र तक सीमित विषय नहीं रह गई है, बल्कि यह आपदा जोखिम प्रबंधन तथा जलवायु अनुकूलन की एक प्रमुख प्राथमिकता बन चुकी है।

पंजाब में बाढ़ : आजीविका और खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव

पंजाब में आई बाढ़ ने यह स्पष्ट किया कि आपदा पूर्व तैयारी का महत्व केवल जन-धन की प्रत्यक्ष हानि को कम करने तक सीमित नहीं है। इस घटना ने यह भी रेखांकित किया कि चरम मौसमीय घटनाएँ बहुत कम समय में आजीविका की हानि तथा दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा संबंधी जोखिमों का कारण बन सकती हैं। पंजाब भारत के कुल गेहूँ उत्पादन में लगभग 15-20 प्रतिशत तथा राष्ट्रीय धान उत्पादन में लगभग 10-12 प्रतिशत का योगदान देता है। साथ ही, यह देश की सार्वजनिक खाद्यान्न खरीद प्रणाली का भी एक प्रमुख आधार है। हिमालय के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में हुई अत्यधिक वर्षा के परिणामस्वरूप व्यापक बाढ़ एवं जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे लगभग 2.21 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित हुई। इसके परिणामस्वरूप खाद्य उपलब्धता, सार्वजनिक खरीद, कृषि बाजारों तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पर व्यापक प्रभाव पड़ा।

पंजाब के अनुभव व्यापक नीतिगत दृष्टि से एक महत्वपूर्ण संदेश प्रदान करते हैं। जैसे-जैसे चरम मौसमीय घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ेगी, वैसे-वैसे प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, उपग्रह-आधारित निगरानी, जलवायु-प्रत्यास्थ कृषि, फसल बीमा, पूर्वानुमान के आधार पर कार्रवाई तथा आपदा जोखिम वित्तपोषण में निवेश का महत्व निरंतर बढ़ता जाएगा। आधुनिक पृथ्वी अवलोकन प्रणालियाँ तथा प्रौद्योगिकी युक्त प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियाँ वर्षा, बाढ़, सूखा, मृदा आर्द्रता तथा फसलों पर पड़ने वाले प्रभाव की लगभग वास्तविक समय में निगरानी की हमारी क्षमता को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ बना रही हैं।

चरम मौसमीय घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति आपदा जोखिम वित्तपोषण तथा जलवायु-प्रत्यास्थ कृषि प्रणालियों के महत्व को भी रेखांकित करती है। कृषि क्षेत्र में होने वाली क्षति से उबरने के लिए राहत, क्षतिपूर्ति, आधारभूत संरचना की पुनर्बहाली तथा आजीविका सहायता पर प्रायः बड़े पैमाने पर सार्वजनिक व्यय करना पड़ता है। इसके विपरीत, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, बाढ़ पूर्वानुमान, जलवायु-प्रत्यास्थ कृषि पद्धतियों, फसल बीमा, उपग्रह-आधारित फसल निगरानी तथा पूर्वानुमान पर आधारित कार्रवाई में किया गया निवेश कृषि हानियों को उल्लेखनीय रूप से कम करने तथा पुनर्बहाली प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। इसके साथ ही, स्थानीय स्तर पर आपदा पूर्व तैयारी को सुदृढ़ करना तथा जोखिम के प्रति सतर्कता पूर्वक कृषि नियोजन को बढ़ावा देना कृषि क्षेत्र की प्रत्यास्थता को सशक्त बनाने के लिए समान रूप से आवश्यक है।

साइबर जोखिम आपदा प्रबंधन : परस्पर संबद्ध डिजिटल विश्व में प्रत्यास्थता का निर्माण

डॉ. विशाल काटेकर
शोध सहयोगी, एनआईडीएम

1. परिचय

क्लाउड कंप्यूटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा विश्लेषण, उपग्रह संचार तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी डिजिटल प्रौद्योगिकियों में हाल के वर्षों में हुई तीव्र प्रगति ने सरकारों, व्यवसायों, महत्वपूर्ण अवसंरचना क्षेत्रों तथा समाज में डिजिटल रूपांतरण की प्रक्रिया को अभूतपूर्व गति प्रदान की है। इन डिजिटल प्रौद्योगिकियों के व्यापक उपयोग से कार्यकुशलता, परस्पर संपर्क तथा सेवा प्रदायगी में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। किंतु इसके साथ ही साइबर आपदाओं से संबंधित संवेदनशीलताओं तथा जोखिमों में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वैश्विक स्तर पर यह देखा गया है कि साइबर घटनाओं में आवश्यक सेवाओं को बाधित करने, महत्वपूर्ण अवसंरचना को क्षति पहुँचाने, जन-विश्वास को कमजोर करने तथा अनेक क्षेत्रों में क्रमिक एवं व्यापक प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता होती है। वर्तमान परस्पर संबद्ध डिजिटल विश्व में किसी एक स्थान या देश में होने वाला साइबर हमला अन्य देशों की डिजिटल प्रणालियों को भी प्रभावित कर सकता है। आज साइबर जोखिम एक ऐसे महत्वपूर्ण आपदा जोखिम के रूप में उभरकर सामने आया है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता, जन-सुरक्षा तथा सामाजिक कल्याण पर व्यापक प्रभाव डाल सकता है। इसलिए साइबर जोखिम आपदा प्रबंधन की अवधारणा आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिरोधक क्षमता निर्माण की रणनीतियों का एक अनिवार्य एवं अभिन्न अंग बन गई है।

2. साइबर जोखिम आपदा प्रबंधन की अवधारणा

साइबर जोखिम आपदा प्रबंधन से अभिप्राय उस व्यवस्थित प्रक्रिया से है, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रणालियों, आधारभूत अवसंरचना तथा आवश्यक सेवाओं को प्रभावित करने वाली साइबर घटनाओं की पहचान, जोखिम आकलन, निवारण, पूर्व तैयारी, प्रतिक्रिया तथा पुनर्बहाली से संबंधित सभी उपायों को समाहित किया जाता है। यह साइबर सुरक्षा तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के सिद्धांतों का एकीकृत दृष्टिकोण अपनाते हुए साइबर हमलों, तकनीकी विफलताओं, मानवीय त्रुटियों तथा प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न जोखिमों का समुचित प्रबंधन सुनिश्चित करता है। जैसे-जैसे समाज डिजिटल प्रौद्योगिकियों पर अधिकाधिक निर्भर होता जा रहा है, साइबर जोखिम प्रबंधन केवल एक तकनीकी विषय न रहकर राष्ट्रीय प्रत्यास्थता का एक महत्वपूर्ण आधार बन गया है। साइबर जोखिम अनेक स्रोतों से उत्पन्न हो सकते हैं, जिनमें साइबर युद्ध, साइबर जासूसी, रैनसमवेयर हमले, साइबर अपराध, आंतरिक खतरों, सॉफ्टवेयर की कमजोरियाँ, आपूर्ति शृंखला से जुड़े समझौते तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता-युक्त साइबर हमले प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त, डिजिटल अवसंरचना बाढ़, भूकम्प, चक्रवात तथा अन्य चरम मौसमीय घटनाओं जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति भी संवेदनशील होती है (चित्र-1)। पारंपरिक आपदाओं के विपरीत, साइबर घटनाएँ परस्पर संबद्ध डिजिटल नेटवर्कों के माध्यम से अत्यंत तीव्र गति से फैल सकती हैं और अनेक क्षेत्रों में क्रमिक विफलताओं को जन्म दे सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक स्तर पर सेवाएँ एवं प्रणालियाँ प्रभावित हो सकती हैं।

3. साइबर खतरों का विकसित होता परिदृश्य

पिछले एक दशक के दौरान साइबर हमलों की आवृत्ति, जटिलता तथा व्यापकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, वित्त, दूरसंचार तथा आपातकालीन सेवाओं जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र साइबर हमलावरों के प्रमुख लक्ष्य बनते जा रहे हैं। WannaCry रैनसमवेयर हमले जैसी घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि साइबर व्यवधान वैश्विक स्तर पर आवश्यक सेवाओं को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), क्लाउड कंप्यूटिंग, स्मार्ट सिटी तथा स्वायत्त प्रणालियों के बढ़ते उपयोग ने साइबर खतरों के दायरे का विस्तार कर दिया है। साथ ही, कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा तंत्र विकसित करने वाले पक्षों और साइबर हमलावरों, दोनों को उन्नत क्षमताएँ प्रदान कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप साइबर परिवेश पहले की तुलना में अधिक जटिल, गतिशील तथा चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है।

4. आपदा जोखिम के रूप में साइबर जोखिम

परंपरागत रूप से आपदा प्रबंधन का प्रमुख ध्यान बाढ़, भूकम्प, सूखा तथा चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं पर केंद्रित रहा है। किंतु तीव्र डिजिटलीकरण के कारण भौतिक और साइबर क्षेत्रों के बीच का अंतर लगातार कम होता जा रहा है। उदाहरण के लिए, यदि विद्युत ग्रिड पर साइबर हमला होता है, तो इससे विद्युत आपूर्ति बाधित

हो सकती है, जल वितरण प्रणालियाँ प्रभावित हो सकती हैं, परिवहन नेटवर्क अवरुद्ध हो सकते हैं तथा स्वास्थ्य सेवाएँ भी गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती हैं। इसी प्रकार, संचार प्रणालियों पर होने वाले साइबर हमले आपदाओं के दौरान आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यों तथा महत्वपूर्ण सूचनाओं के समयबद्ध प्रसार में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। इन परस्पर निर्भरताओं के कारण क्रमिक प्रभाव उत्पन्न होते हैं, जो प्रारंभिक साइबर घटना के दुष्प्रभावों को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इसलिए साइबर जोखिमों को केवल सूचना सुरक्षा की समस्या के रूप में नहीं, बल्कि प्रणालीगत आपदा जोखिम के रूप में देखते हुए उनका समग्र प्रबंधन किया जाना आवश्यक है।

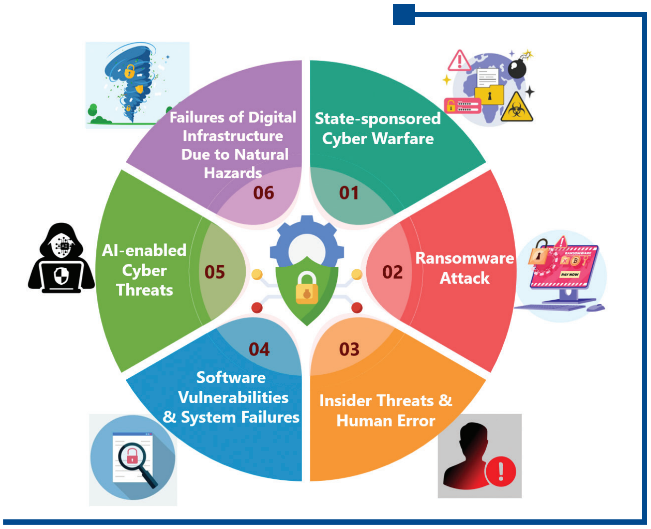

चित्र 1: साइबर जोखिमों के स्रोत।

5. महत्वपूर्ण अवसंरचना एवं साइबर प्रत्यास्थता

महत्वपूर्ण अवसंरचना किसी भी राष्ट्र के विकास, आर्थिक स्थिरता, जन-सुरक्षा तथा सामाजिक कल्याण की रीढ़ है। जैसे-जैसे ये क्षेत्र परस्पर संबद्ध डिजिटल प्रौद्योगिकियों पर अधिक निर्भर होते जा रहे हैं, वैसे-वैसे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना एक रणनीतिक प्राथमिकता बन गया है। साइबर प्रत्यास्थता से तात्पर्य प्रणालियों, संगठनों तथा समाज की उस क्षमता से है, जिसके माध्यम से वे साइबर व्यवधानों का पूर्वानुमान लगा सकें, उनका सामना कर सकें, प्रभावी प्रतिक्रिया दे सकें, उनसे शीघ्र उबर सकें तथा बदलती परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को तैयार कर सकें। पारंपरिक साइबर सुरक्षा मुख्यत: साइबर घटनाओं की रोकथाम पर केंद्रित होती है, जबकि साइबर प्रत्यास्थता का उद्देश्य व्यवधान की स्थिति में भी आवश्यक सेवाओं एवं कार्यों की निरंतरता बनाए रखना तथा त्वरित पुनर्बहाली सुनिश्चित करना है। साइबर प्रत्यास्थता प्राप्त करने के लिए जोखिम आकलन, सुरक्षा-आधारित अभिकल्प, व्यावसायिक निरंतरता योजना, आपदा पुनर्बहाली तंत्र, वैकल्पिक व्यवस्था, निरंतर निगरानी, खतरे की जानकारी, घटना प्रतिक्रिया क्षमता तथा मानव संसाधन क्षमता विकास जैसे उपाय अत्यंत आवश्यक हैं। सुदृढ़ प्रणालियाँ केवल साइबर घटनाओं को रोकने के लिए ही नहीं, बल्कि व्यवधान उत्पन्न होने पर उनके प्रभावों को सहन करने तथा न्यूनतम समय में सामान्य स्थिति में लौटने के लिए भी डिज़ाइन किए जाते हैं।

6. चुनौतियाँ एवं आगे की राह

साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद प्रभावी साइबर जोखिम आपदा प्रबंधन के समक्ष अनेक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। इनमें तीव्र गति से विकसित हो रहे साइबर खतरे, कुशल विशेषज्ञों की कमी, सीमित जन-जागरूकता, सूचनाओं के अपर्याप्त आदान-प्रदान, नियामकीय कमियाँ तथा महत्वपूर्ण अवसंरचना क्षेत्रों के बीच बढ़ती परस्पर निर्भरता प्रमुख हैं। इन चुनौतियों का प्रभावी समाधान सरकारों, उद्योगों, शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों तथा नागरिक समाज के मध्य सुदृढ़ सहयोग स्थापित किए बिना संभव नहीं है। भविष्य की दृष्टि से आवश्यक है कि साइबर प्रत्यास्थता को आपदा जोखिम न्यूनीकरण की रणनीतियों का अभिन्न अंग बनाया जाए। इसके लिए महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा को सुदृढ़ करना, साइबर घटनाओं के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता विकसित करना तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भू-स्थानिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल ट्विन जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, अंतराष्ट्रीय सहयोग, क्षमता निर्माण, साइबर स्वच्छता को बढ़ावा देना तथा नियमित रूप से साइबर संकट अनुकरण अभ्यास आयोजित करना एक परस्पर संबद्ध डिजिटल विश्व में साइबर प्रत्यास्थता को सुदृढ़ करने के लिए अनिवार्य है।

एनआईडीएम की वैश्विक पहुंच: सीमाओं से परे आपदा-रोधी क्षमता का विस्तार

सुश्री नाज़िया खान, *वरिष्ठ परामर्शदाता एवं आईपीआरओ, एनआईडीएम*
डॉ. श्वेता रानी, *परामर्शदाता, एनआईडीएम*

आज के बढ़ते परस्पर-संबद्ध विश्व में आपदाएँ अब भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं रह गई हैं। जलवायु-जनित आपात स्थितियों से लेकर जटिल मानवीय संकटों तक, वैश्विक सहयोग, आपसी सीख तथा सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। माननीय प्रधानमंत्री के आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु दस सूत्रीय एजेंडा पर आधारित तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंडाई फ्रेमवर्क (2015-2030) के अनुरूप, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ज्ञान के आदान-प्रदान, क्षमता विकास तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में भारत की वैश्विक नेतृत्वकारी भूमिका को निरंतर मजबूत कर रहा है।

समय के साथ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान से विकसित होकर आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त उत्कृष्टता केंद्र के रूप में स्थापित हुआ है। संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (यूएनडीआरआर), उसके वैश्विक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (गेटी) तथा अनेक अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ रणनीतिक साझेदारियों के माध्यम से संस्थान ने सहयोगात्मक अनुसंधान, नीतिगत संवाद, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान के लिए गतिशील मंच तैयार किए हैं।

इस यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम के तहत आपदा जोखिम प्रबंधन पर चार प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सफल आयोजन रहा है। इन प्रमुख कार्यक्रमों ने एशिया और अफ्रीका के साझेदार देशों के सरकारी अधिकारियों, आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों, नीति-निर्माताओं तथा व्यावहारिक कार्यकर्ताओं (प्रैक्टिशनर्स) को एक साझा मंच पर एकत्रित किया है। इन कार्यक्रमों ने दक्षिण-दक्षिण सहयोग तथा वैश्विक क्षमता निर्माण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को और अधिक सुदृढ़ किया है।

इसी गौरवपूर्ण परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने 1 से 12 जून, 2026 तक आपदा जोखिम प्रबंधन पर चौथे आईटीईसी प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यह कार्यक्रम एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक, श्री मधुप व्यास (भा.प्र.से.) के दूरदर्शी नेतृत्व में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का समन्वयन श्री शेखर चतुर्वेदी, सहायक प्राध्यापक, एनआईडीएम द्वारा किया गया, जबकि डॉ. सुषमा गुलेरिया, सह-प्राध्यापक, एनआईडीएम ने सह-समन्वयक के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम के सफल आयोजन में सुश्री नाज़िया खान, आईपीआरओ, एनआईडीएम का भी उल्लेखनीय सहयोग रहा।

इस कार्यक्रम में ज़ाम्बिया, तंज़ानिया, नाइजीरिया, मलावी, मोज़ाम्बिक, म्यांमार, कंबोडिया, श्रीलंका, किंगडम ऑफ इस्वातिनी, सिएरा लियोन तथा सीरिया से आए वरिष्ठ अधिकारियों एवं आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों ने भाग लिया, जिससे सीखने का एक शानदार और विविधतापूर्ण सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण हुआ। यह केवल एक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक ऐसा सशक्त मंच था जहाँ विभिन्न देशों के अनुभवों का संगम देखने को मिला। प्रतिभागियों ने नवीन एवं प्रभावी कार्य-पद्धतियों का आदान-प्रदान किया, समान चुनौतियों पर सार्थक विचार-विमर्श किया तथा राष्ट्रीय सीमाओं से परे दीर्घकालिक प्रोफेशनल संबंध स्थापित किए।

एक व्यापक क्षमता निर्माण पहल के रूप में डिज़ाइन किए गए इस कार्यक्रम में भारत के समग्र आपदा प्रबंधन तंत्र का परिचय विशेषज्ञों द्वारा संचालित सत्रों के माध्यम से कराया गया। इन सत्रों में आपदा जोखिम शासन, संस्थागत ढाँचा, खतरा, संवेदनशीलता एवं क्षमता आकलन, घटना प्रतिक्रिया प्रणाली, जलवायु प्रत्यास्थता, शहरी बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व चेतावनी प्रणाली तथा उभरते आपदा जोखिमों जैसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त, फील्ड विज़िट और संवादात्मक चर्चाओं ने प्रतिभागियों के सीखने के अनुभव को और अधिक समृद्ध बनाया।

इन गतिविधियों ने नीति और व्यवहार के मध्य प्रभावी सेतु स्थापित करते हुए प्रतिभागियों की समझ को और अधिक गहराई प्रदान की तथा आपदा प्रत्यास्थता के प्रति भारत के समग्र दृष्टिकोण को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया।

इन पहलों का प्रभाव केवल प्रशिक्षण कक्ष तक सीमित नहीं है। प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम संस्थागत क्षमताओं को सुदृढ़ करता है, दीर्घकालिक साझेदारियों को प्रोत्साहित करता है तथा आपदा जोखिम को कम करने और प्रत्यास्थता को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध आपदा प्रबंधन पेशेवरों के एक निरंतर विकसित हो रहे वैश्विक समुदाय के निर्माण में योगदान देता है। प्रतिभागी अपने-अपने देशों में केवल उन्नत तकनीकी ज्ञान के साथ ही नहीं लौटते, बल्कि सुदृढ़ व्यावसायिक नेटवर्क तथा सहयोगात्मक कार्रवाई के प्रति नए उत्साह और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ भी लौटते हैं।

जैसे-जैसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान अपनी अंतरराष्ट्रीय पहुँच का विस्तार कर रहा है, वैसे-वैसे आईटीईसी प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में भारत एक उभरते हुए वैश्विक ज्ञान साझेदार के रूप में अपनी सशक्त भूमिका को प्रमाणित कर रहा है। नवाचार को प्रोत्साहित करने, मिलकर सीखन को बढ़ावा देने तथा विभिन्न देशों की संस्थागत क्षमताओं को सुदृढ़ करने के माध्यम से एनआईडीएम, माननीय प्रधानमंत्री के आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु दस सूत्रीय एजेंडा की परिकल्पना को सार्थक वैश्विक कार्रवाई में रूपांतरित कर रहा है। इसके माध्यम से सशक्त संस्थानों, सुदृढ़ समुदायों तथा सभी के लिए अधिक सुरक्षित और सतत् भविष्य के निर्माण की दिशा में ठोस योगदान दिया जा रहा है।

''आज सीमाओं के पार साझा किया गया ज्ञान, कल राष्ट्रों की सुदृढ़ प्रत्यास्थता का आधार बनता है।''

भारत में सीबीआरएन तैयारियों की मजबूती : पारंपरिक आपदा जोखिमों से आगे की परिकल्पना

डॉ. कुलदीप चौरसिया, *एसोसिएट प्रोफेसर, एनआईडीएम*
एवं सुश्री विनीता कुमारी, *शोध सहयोगी, एनआईडीएम*

जब हम भारत में आपदाओं के बारे में विचार करते हैं, तो सामान्यत: बाढ़, चक्रवात, भूकम्प तथा हीटवेव जैसी आपदाएँ हमारे मन में आती हैं। किंतु इसके अतिरिक्त एक अन्य श्रेणी के जोखिम भी हैं, जो अत्यंत गंभीर एवं संभावित रूप से विनाशकारी हैं। इन्हें रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल एवं नाभिकीय (सीबीआरएन) आपात स्थिति के रूप में जाना जाता है।

यद्यपि सीबीआरएन आपात स्थिति अपेक्षाकृत कम घटित होती हैं, फिर भी भारत की भोपाल गैस त्रासदी, चेरनोबिल तथा फुकुशिमा की परमाणु दुर्घटनाएँ, टोक्यो सरीन गैस हमला, इबोला प्रकोप तथा कोविड-19 महामारी जैसी घटनाएँ इन आपात स्थितियों के अत्यंत गंभीर प्रभावों को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं। इन घटनाओं (जैसा कि तालिका-1 में दर्शाया गया है) के परिणामस्वरूप व्यापक जनहानि, स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएँ, पर्यावरणीय क्षति तथा आर्थिक अव्यवस्था उत्पन्न हुई, जिनके अनेक प्रभाव कई वर्षों तक बने रहे। ये घटनाएँ इस बात को रेखांकित करती हैं कि प्रभावी पूर्व तैयारी, समयबद्ध पूर्व चेतावनी, प्रशिक्षित आपदा मोचन बल तथा सुदृढ़

आपातकालीन प्रबंधन प्रणाली ऐसी आपातस्थितियों से निपटने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

भारत में तीव्र औद्योगिकीकरण तथा परिवहन नेटवर्क के निरंतर विस्तार के साथ रसायनों एवं अन्य खतरनाक पदार्थों के उपयोग और परिवहन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रेडियोधर्मी पदार्थों का व्यापक उपयोग अस्पतालों, अनुसंधान संस्थानों तथा विभिन्न उद्योगों में किया जाता है, जबकि रसायनों का प्रतिदिन सड़कों, रेलमार्गों, बंदरगाहों तथा हवाई अड्डों के माध्यम से बड़े पैमाने पर परिवहन होता है। यद्यपि इनके सुरक्षित उपयोग एवं परिवहन के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय लागू हैं, फिर भी दुर्घटनाओं की संभावना पूरी तरह समाप्त नहीं की जा सकती। इसलिए आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से सीबीआरएन आपदा पूर्व तैयारी को सुदृढ़ करना अत्यंत आवश्यक है।

नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीबीआरएन आपात स्थितियों से निपटने की तैयारी को मज़बूत करने पर हाल ही में हुई चर्चा में इस बात पर जोर दिया गया कि सिर्फ उपकरणों की खरीद पर्याप्त नहीं है। असल में, प्रभावी तैयारी के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन, स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रियाएं तथा नियमित मॉक अभ्यास समान रूप से आवश्यक हैं। चर्चा के दौरान यह भी रेखांकित किया गया कि क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने से पूर्व उपलब्ध क्षमताओं का आकलन तथा प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस दृष्टि से, किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना बनाने से पहले उपलब्ध क्षमताओं तथा विद्यमान कमियों का व्यवस्थित आकलन अत्यंत आवश्यक है। यह कार्य प्रशिक्षण आवश्यकता आकलन के माध्यम से किया जा सकता है, जो संभावित जोखिमों, प्रशिक्षण आवश्यकताओं तथा परिचालन संबंधी चुनौतियों की पहचान करने में सहायक होता है।

इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षित आंतरिक आपदा प्रतिक्रिया दल, स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रियाएं, उपकरणों की सुव्यवस्थित सूची तथा नियमित टेबल-टॉप अभ्यास और मॉक ड्रिल सीबीआरएन आपातस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने की संस्थागत क्षमता को और अधिक सुदृढ़ बना सकते हैं। ऐसे उपाय देश के हवाई अड्डों, समुद्री बंदरगाहों, स्थल बंदरगाहों तथा अन्य महत्वपूर्ण अवसंरचना परिसरों में सीबीआरएन आपदा पूर्व तैयारी को सशक्त बनाने में भी समान रूप से उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, प्रौद्योगिकी की भूमिका को किसी भी प्रकार से नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं मशीन लर्निंग के अनुप्रयोगों का उपयोग विश्वभर में बड़े डेटा समूहों के विश्लेषण तथा असामान्य प्रतिरूपों की पहचान के लिए निरंतर बढ़ रहा है। सीबीआरएन आपातस्थितियों के संदर्भ में ये प्रौद्योगिकियाँ सेंसरों से प्राप्त आँकड़ों के विश्लेषण, असामान्य विकिरण स्तरों का पता लगाने, खतरनाक रसायनों के रिसाव की निगरानी करने तथा संभावित प्रभाव क्षेत्रों के आकलन में प्रभावी सहयोग प्रदान कर सकती हैं। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ऐसी प्रणालियाँ मानव-आधारित निर्णय प्रक्रिया का विकल्प नहीं हैं, बल्कि समय-संवेदी परिस्थितियों में निर्णयकर्ताओं को त्वरित एवं विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध करवाकर निर्णय लेने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाती हैं।

एक अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र सीबीआरएन समेकित पूर्व चेतावनी एवं निर्णय-सहायक प्रणाली का विकास है, जो सीबीआरएन जोखिमों का समय रहते पता लगाने, उनकी निरंतर निगरानी करने तथा संभावित प्रभावों का पूर्वानुमान लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ऐसी उन्नत प्रणालियाँ विकिरण निगरानी उपकरणों, रासायनिक सेंसरों, मौसम पूर्वानुमानों, उपग्रह चित्रों तथा भू-स्थानिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मानचित्रण उपकरणों सहित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं का एकीकृत उपयोग कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी औद्योगिक इकाई से खतरनाक रसायनों का रिसाव होता है, तो एआई-युक्त प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली पवन की गति, वायुमंडलीय दाब, तापमान तथा आर्द्रता जैसे मौसम संबंधी आँकड़ों का विश्लेषण कर रासायनिक प्रसार की संभावित दिशा एवं सीमा का अनुमान लगा सकती है। इस प्रकार प्राप्त जानकारी संबंधित प्राधिकारियों को समय पर चेतावनी जारी करने, जोखिमग्रस्त क्षेत्रों की पहचान करने तथा आवश्यक सुरक्षात्मक उपायों की प्रभावी योजना बनाने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इसके साथ ही, आपदा प्रबंधन संस्थानों को अनुसंधान एवं वैज्ञानिक संस्थाओं के सहयोग से भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप व्यावहारिक एवं प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान विकसित करने चाहिए। इस दिशा में केवल आपातस्थितियों के दौरान प्रभावी प्रतिक्रिया देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि नियमित जोखिम आकलन, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, मॉक अभ्यास तथा ज्ञान-साझाकरण के माध्यम से आपदा पूर्व तैयारी की सुदृढ़ संस्कृति का विकास करना भी समान रूप से आवश्यक है।

तालिका-1 : विश्व की प्रमुख सीबीआरएन आपातस्थितियाँ एवं उनके प्रभाव

वर्ष	घटना	प्रकार	स्थान	प्रमुख प्रभाव
1984	भोपाल गैस त्रासदी	रासायनिक	भारत	विश्व की सबसे भीषण औद्योगिक आपदाओं में से एक; हजारों लोगों की मृत्यु तथा पाँच लाख से अधिक लोगों पर दीर्घकालिक स्वास्थ्य संबंधी प्रतिकूल प्रभाव।
1986	चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना	रेडियोलॉजिकल/नाभिकीय	यूक्रेन (तत्कालीन सोवियत संघ)	व्यापक स्तर पर रेडियोधर्मी विकिरण का उत्सर्जन, बड़े पैमाने पर लोगों का विस्थापन तथा दीर्घकालिक पर्यावरणीय एवं स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव।
1995	टोक्यो मेट्रो सरीन गैस हमला	रासायनिक	जापान	आतंकवादी हमले में रासायनिक एजेंटों का उपयोग; हजारों लोग प्रभावित हुए तथा व्यापक जन-आतंक की स्थिति उत्पन्न हुई।
2011	फुकुशिमा दाइची परमाणु दुर्घटना	रेडियोलॉजिकल/नाभिकीय	जापान	भूकम्प एवं सुनामी के पश्चात् परमाणु दुर्घटना; बड़े पैमाने पर निकासी तथा दीर्घकालिक पुनर्बहाली प्रयास की आवश्यकता
2014-2016	इबोला प्रकोप	जैविक	पश्चिमी अफ्रीका	28,000 से अधिक मामले दर्ज; बीमारी की निगरानी और जन स्वास्थ्य तैयारियों के महत्व पर ज़ोर।
2020	एलजी पॉलिमर्स स्टाइरीन गैस रिसाव	रासायनिक	विशाखापत्तनम, भारत	हजारों लोग गैस के संपर्क में आए, जनहानि हुई तथा आसपास के क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करना पड़ा।
2020-2023	कोविड-19 महामारी	जैविक	वैश्विक	अभूतपूर्व स्वास्थ्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव; विश्वभर में अरबों लोग प्रभावित हुए।

प्रशिक्षणार्थियों के अनुभव

आपदा जोखिम प्रबंधन पर 15 वां समग्र पाठ्यक्रम

नामः ***श्री मोहित सिंह***
पदः ***संयुक्त निदेशक***
क्वालिटी काउंसिल ऑफ़ इंडिया

यह ट्रेनिंग मेरे लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक और दृष्टिकोण को व्यापक बनाने वाला अनुभव रहा। इस कोर्स से मुझे आपदा जोखिम प्रबंधन की अच्छी तरह से व्यवस्थित और व्यापक समझ मिली, जिसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम और बचाव की रणनीतियों से लेकर प्रतिक्रिया की योजना बनाने और समुदाय की मज़बूती तक सब कुछ शामिल था। कमज़ोर समुदायों-जैसे महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगजनों पर हुए सेशन ने आपदा प्रबंधन में मानवीय पहलू को उजागर किया, जिसे अक्सर नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, विजयवाड़ा के निकट बाढ़ प्रभावित गाँव के क्षेत्रीय भ्रमण से मुझे बहुमूल्य व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हुआ। इस भ्रमण ने यह स्पष्ट किया कि प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए सामुदायिक स्तर पर पूर्व तैयारी और स्थानीय सहभागिता कितनी महत्वपूर्ण है।

नामः ***श्री अभिषेक कुमार आनंद***
पदः ***निदेशक (वित्त)***
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखंड सरकार

यह कार्यक्रम एक ज्ञानवर्धक और समृद्ध अनुभव रहा है। इसने आपदा की तैयारी और उससे निपटने के तकनीकी, प्रशासनिक, वित्तीय और सामुदायिक पहलुओं को मिलाकर आपदा जोखिम प्रबंधन की व्यापक समझ प्रदान की। स्वास्थ्य आपात स्थितियों, आपदा के दौरान पोषण और कमज़ोर वर्गों (जैसे महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और दिव्यांगजन) की सुरक्षा पर हुई चर्चाएँ विशेष रूप से जानकारीपूर्ण थीं। इन चर्चाओं ने समावेशी योजना बनाने और ऐसे मज़बूत सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र की आवश्यकता पर ज़ोर दिया जो बदलती आपदा स्थितियों का सामना करने में सक्षम हों।

आपदा जोखिम प्रबंधन पर 16 वां समग्र पाठ्यक्रम

नामः ***डॉ. के. शशिकुमार***
पदः ***आईएफएस***
सीसीएफ, गुजरात

एनआईडीएम का 16वां समग्र पाठ्यक्रम बहुत जानकारी युक्त और अच्छी तरह से तैयार किया गया था। वाइल्डलाइफ़ डीआरआर और जंगल की आग के प्रबंधन पर एक्सपर्ट सेशन और केस स्टडीज़ ने गुजरात वन विभाग के लिए सीधे तौर पर काम आने वाले प्रैक्टिकल तरीके बताए। इन जानकारियों से ज़मीनी स्तर पर हमारे डीआरआर प्रयासों को मज़बूती मिलेगी। इस अवसर के लिए एनआईडीएम का धन्यवाद।

प्रशिक्षणार्थियों के अनुभव

चौथा ITEC, आपदा जोखिम प्रबंधन पर समग्र पाठ्यक्रम

नामः टी. श्रीराजीवन
पदः असिस्टेंट सेक्रेटरी एसएलएएस
आपदा प्रबंधन डिवीजन, रक्षा मंत्रालय, श्रीलंका

मैं सीसीडीआरएम के चौथे आईटीईसी बैच को आयोजित करने के लिए एनआईडीएम, नई दिल्ली और आईटीईसी प्रोग्राम का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यह प्रोग्राम बहुत ज्ञानवर्धक था और इससे आपदा जोखिम कम करने, तैयारी, प्रतिक्रिया, रिकवरी और प्रत्यास्थता बनाने के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिली। एनडीएमए और एनडीआरएफ के दौरों से भारत के आपदा प्रबंधन ढांचे और ऑपरेशनल तैयारी के बारे में व्यावहारिक जानकारी मिली। मुझे उत्तर भारतीय खाने का असली स्वाद चखने का मौका भी मिला, जिसने प्रोग्राम में एक सांस्कृतिक पहलू जोड़ा। एनआईडीएम हॉस्टल में सुरक्षित, आरामदायक और अच्छी तरह से बनाए रखे गए आवास ने पूरे कोर्स के दौरान सीखने के लिए एक सुखद माहौल बनाने में काफी योगदान दिया। इसके अलावा, लाल किले और ताजमहल की सांस्कृतिक यात्राओं ने भारत के समृद्ध इतिहास और विरासत के बारे में यादगार अनुभव प्रदान किए। सीखने का बेहतरीन अनुभव प्रदान करने के लिए मैं फैकल्टी, रिसोर्स पर्सन और आयोजन टीम के समर्पण की बहुत सराहना करता हूँ।

नामः सुश्री अलाबेडे ओलासुन्कानमी राफियात
पदः वरिष्ठ अधिकारी
व्यवसाय विकास विभाग, नाइजीरिया

मैं आपदा प्रबंधन पर हाल ही में संपन्न हुए शानदार दो-सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए दिल से सराहना व्यक्त करना चाहती हूँ। सत्रों का आयोजन और उनकी बारीकी सचमुच प्रभावशाली थी। हर विषय को स्पष्टता और गहराई के साथ प्रस्तुत किया गया, जिससे आपदा प्रबंधन के तरीकों के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिली। प्रशिक्षकों की विशेषज्ञता और प्रतिभागियों के बीच बने सहयोगपूर्ण माहौल ने सीखने के अनुभव को और बेहतर बनाया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफल बनाने में आपके समर्पण और कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि इससे प्राप्त ज्ञान मेरे भविष्य के प्रयासों में बहुत काम आएगा।

नामः सुश्री नीमा मसाव
पदः अर्थशास्त्री
प्रधानमंत्री कार्यालय, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ़ तंजानिया

मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ डिज़ास्टर मैनेजमेंट में शॉर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेने का मौका मिलने पर अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। यह प्रोग्राम बहुत अच्छे ढंग से तैयार किया गया था और इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। इसने मुझे डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट और मुश्किल हालात से निपटने की रणनीतियों के बारे में गहरी जानकारी और व्यापक नज़रिया दिया। इसने विकास की योजना बनाने और पॉलिसी बनाने में डिज़ास्टर रिस्क कम करने के तरीकों को शामिल करने की मेरी समझ को काफ़ी मज़बूत किया है, खासकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संदर्भ में। जाने-माने एक्सपर्ट्स के इंटरैक्टिव सेशन बहुत जानकारीपूर्ण और प्रैक्टिकल थे, जिन्होंने थ्योरी और असल ज़िंदगी में उनके इस्तेमाल के बीच के अंतर को कम किया। मैं उन विज़िट्स के लिए भी बहुत आभारी हूँ जिनसे मुझे डिज़ास्टर से निपटने की तैयारी के सिस्टम और मौसम से जुड़ी सेवाओं के बारे में सीधे तौर पर ज़रूरी जानकारी मिली, जिससे सीखने का अनुभव और भी बेहतर हुआ। पढ़ाई-लिखाई के अलावा, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को जानने-समझने के मौके ने इस प्रोग्राम को सचमुच यादगार और प्रेरणादायक बना दिया। मैं एनआईडीएम को उनकी शानदार मेहमाननवाज़ी, बेहतरीन तालमेल और सीखने के इतने शानदार अनुभव के लिए दिल से धन्यवाद देती हूँ।

प्रशिक्षणार्थियों के अनुभव

चौथा ITEC, आपदा जोखिम प्रबंधन पर समग्र पाठ्यक्रम

नाम: ***श्री नीमा शेरिंग***
पद: ***जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी***
स्थानीय शासन एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मोंगार, भूटान

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) द्वारा 1 से 12 जून, 2026 तक आयोजित व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम अत्यंत ज्ञानवर्धक एवं प्रभावी रहा। इस कार्यक्रम ने आपदा जोखिम प्रबंधन के महत्वपूर्ण आयामों, जैसे—जोखिम आकलन, आपदा पूर्व तैयारी, जोखिम न्यूनीकरण, आपदा प्रतिक्रिया, पुनर्बहाली तथा बिल्ड बैक बेटर दृष्टिकोण के प्रति मेरी समझ को और अधिक सुदृढ़ किया।

पाठ्यक्रम की विषयवस्तु, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), राष्ट्रीय भूकम्प विज्ञान केंद्र (एनसीएस), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) तथा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) जैसे संस्थानों के शैक्षणिक भ्रमण तथा समूह अभ्यास अत्यंत व्यावहारिक एवं वास्तविक आपदा परिस्थितियों में उपयोगी सिद्ध हुए।

प्रशिक्षण सत्रों के अतिरिक्त, विश्वविख्यात सांस्कृतिक धरोहर ताजमहल का भ्रमण भी मेरे लिए अविस्मरणीय अनुभव रहा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम ने आपदा जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में मेरी व्यावसायिक क्षमताओं को उल्लेखनीय रूप से विकसित किया है। इस उत्कृष्ट एवं उपयोगी प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए मैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

नाम: ***सुश्री एल्पिडा चिपुलुमुत्सो सांबाला***
पद: ***प्रोजेक्ट इंजीनियर***
नॉर्दर्न रीजन वॉटर बोर्ड, मलावी

मैं आईटीईसी के तहत 'कॉम्प्रिहेंसिव डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट' कोर्स के लिए एनआईडीएम टीम की तारीफ़ करती हूँ। इस कोर्स ने मुझे आपदा जोखिम कम करने के सिद्धांतों और उनके व्यावहारिक इस्तेमाल को समझने में मदद की है। कोर्स में कई अहम विषयों को शामिल किया गया, जैसे आपदा जोखिम प्रबंधन के फ्रेमवर्क, आपदा जोखिम कम करने के लिए प्रकृति-आधारित समाधान और आपदा प्रबंधन में GIS का इस्तेमाल। इन सेशन से आपदा के असर को कम करने में जोखिम का पहले से आकलन करने, तैयारी, बचाव के उपाय, प्रतिक्रिया और रिकवरी की रणनीतियों के महत्व के बारे में मेरी समझ बेहतर हुई है। लाल किला, ताजमहल और राष्ट्रपति भवन के दौरों से सांस्कृतिक विरासत को बचाने और राष्ट्रीय संपत्तियों व सार्वजनिक संस्थानों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत बनाने के बारे में अहम जानकारी मिली। एक सिविल इंजीनियर के तौर पर, यहाँ मिली जानकारी इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग, डिज़ाइन और उसे लागू करने में आपदा जोखिम से जुड़ी बातों को शामिल करने में बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी।

नाम: ***सुश्री कैरोलीन मुनकोम्बे***
पद: ***एसएचईक्यू ऑफ़िसर***
ज़ाम्बिया इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी, ज़ाम्बिया

मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए आईटीईसी और एनआईडीएम का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे और मेरे साथ आए लोगों को यह मौका दिया। भारत की मेरी यह पहली यात्रा थी और मैं कई तरह की शंकाओं के साथ यहाँ आई थी। लेकिन, आपकी दयालुता और मेहमानवाज़ी ने मुझे सुरक्षित और स्वागत-भरा महसूस कराया। हम अलग-अलग देशों से आए थे, लेकिन आपने हमारे साथ बहुत सम्मान, गरिमा और प्रोफ़ेशनलिज़्म के साथ व्यवहार किया। 'कॉम्प्रिहेंसिव डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट' कोर्स बहुत जानकारीयुक्त और ज्ञान बढ़ाने वाला था। इससे मिली जानकारी और हुनर मेरे प्रोफ़ेशनल काम में बहुत काम आएंगे और मेरे देश में आपदा जोखिम प्रबंधन की कोशिशों में मदद करेंगे। मैं खास तौर पर फ़ील्ड विज़िट और प्रैक्टिकल सीखने के अनुभवों के लिए आभारी हूँ, जिनसे मुझे भारत के आपदा प्रबंधन सिस्टम, आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र और आपदा जोखिम न्यूनीकरण पहलों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिली। इन बेहतरीन तौर-तरीकों को खुद देखना प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद था।

प्रकृति की देन का वितरण : एनआईडीएम दक्षिणी परिसर के आम बच्चों और अनाथालयों तक पहुँचे

सामुदायिक कल्याण और परिसर के संसाधनों के सार्थक इस्तेमाल को बढ़ावा देने की एक सराहनीय पहल के तहत, एनआईडीएम दक्षिणी परिसर ने स्कूल शिक्षा विभाग के ज़रिए अपने परिसर के बाग से तोड़े गए आम स्कूलों और अनाथालयों में बंटवाए।

मौसमी फलों को एकत्रित कर विभिन्न शैक्षणिक एवं कल्याणकारी संस्थानों में बच्चों के बीच वितरित किया गया, जिससे उन्हें प्रकृति की इस अनमोल सौगात की ताजगी और पोषण का लाभ प्राप्त हो सका। इस पहल ने न केवल आम की उपज का सार्थक उपयोग सुनिश्चित किया, बल्कि बच्चों को पौष्टिक मौसमी फल उपलब्ध कराकर उनके स्वास्थ्य एवं कल्याण में भी योगदान दिया।

यह गतिविधि सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सहभागिता के प्रति एनआईडीएम की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अपने प्राकृतिक संसाधनों के लाभों को परिसर की सीमाओं से बाहर व्यापक समाज तक पहुँचाकर संस्थान सेवा, सहयोग और समावेशिता की भावना को निरंतर प्रोत्साहित कर रहा है तथा समुदाय के साथ अपने संबंधों को और अधिक सुदृढ़ बना रहा है। बच्चों और संस्थानों से प्राप्त मुस्कानें एवं सराहना इस बात का सशक्त स्मरण कराती हैं कि साझा करने के छोटे-से प्रयास भी समाज में सार्थक एवं दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं।

एनआईडीएम प्रकाशन

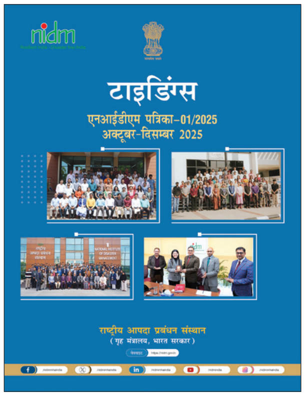

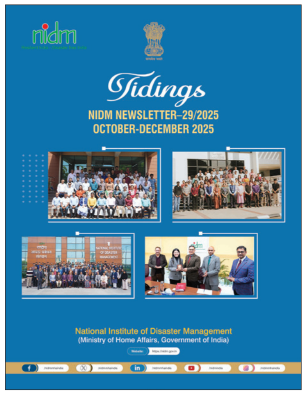

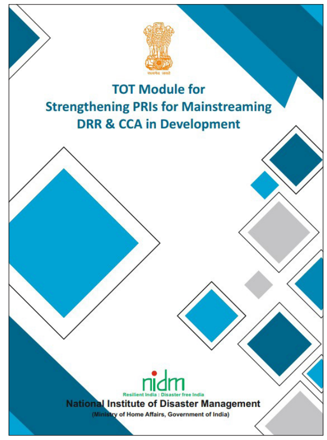

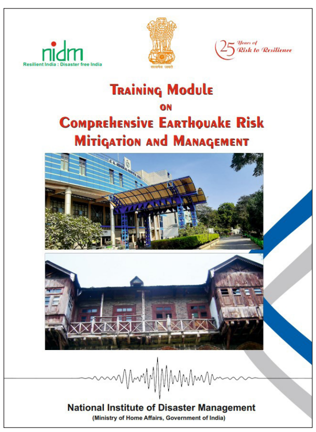

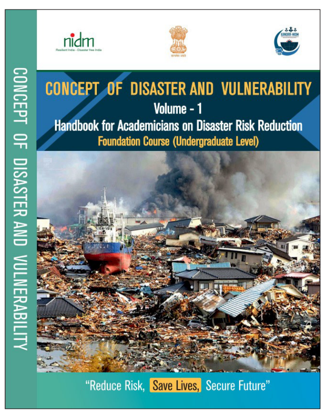

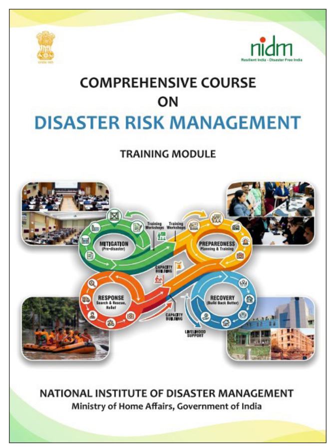

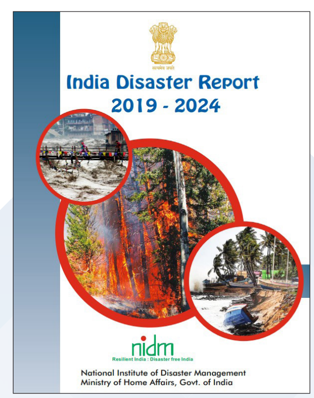

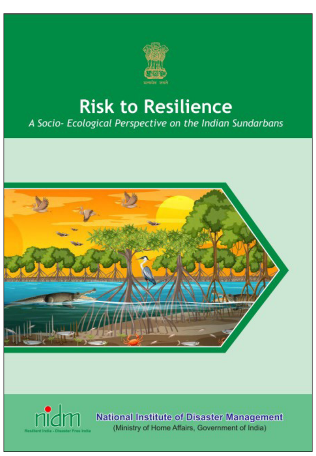

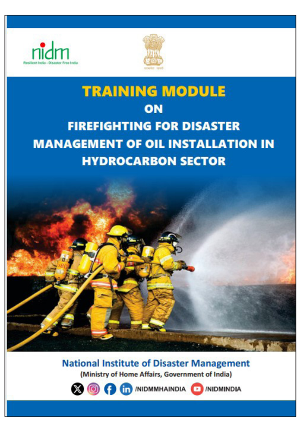

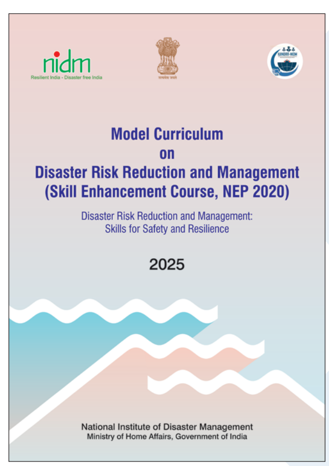

एनआईडीएम पोर्टल्स

- NIDM Training Portal — https://training.nidm.gov.in/
- idrn.nidm.gov.in — India Disaster Resource Network
- India Universities and Institutions Network for Disaster Risk Reduction (IUINDRR) — https://iuin-drr.nidm.gov.in/
- National Platform for Disaster Risk Reduction (NPDRR) — https://npdrr.nidm.gov.in/
- e-Learning Courses on Disaster Risk Management — https://elearning.nidm.gov.in
- Self Study Programme on Disaster Risk Management — https://ssp.nidm.gov.in/

वर्ष 2026-27 के दौरान एनआईडीएम द्वारा आयोजित एवं प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी के लिए कृपया नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करें।

National Institute of Disaster Management

Ministry of Home Affairs, Government of India

nidm — Resilient India - Disaster Free India

"STAY CONNECTED, STAY INFORMED" - FOLLOW US

SCAN ME

LINKEDIN	FACEBOOK	X	INSTAGRAM	YOUTUBE
NIDMMHA	NIDMMHAINDIA	NIDMMHAINDIA	NIDMMHAINDIA	NIDMINDIA

Resilient India - Disaster Free India

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
(गृह मंत्रालय, भारत सरकार)

प्लॉट नं. 15, पॉकेट 3, ब्लॉक बी, सेक्टर–29, रोहिणी, दिल्ली-110042
वेबसाइट : www.nidm.gov.in